



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राप्तिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]
No. 98]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 13, 2012/वैश्व 24, 1934
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 13, 2012/CHAITRA 24, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग भंगालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2012

(अन्तिम निष्कर्ष)

विषय : यूरोपियन यूनियन में उत्पादित या वहां से निर्यातित एनिलिन का आयात करने के संबंध में पाटनरोधी जांच।

सं. 14/39/2010-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात् नियम या पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. पृष्ठभूमि

- यतः मैसर्स गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कं. लि. ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर कर का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली अथवा पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग (जिसे एतदपश्चात् आवेदक/याचिकाकर्ता कहा गया है) की ओर से यूरोपियन यूनियन (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) में उत्पादित या वहां से निर्यातित एनिलिन (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए एक आवेदन दायर किया है। मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स कैमिकल्स लि. ने अभिव्यक्त रूप से इस याचिका का समर्थन किया है। दस्तावेजों से युक्त इस आवेदन की प्राप्ति के बारे में

नियम 5(5) के अनुसार भारत में ईयू का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत में यूरोपियन आयोग के प्रतिनिधिमंडल को इसकी सूचना दे दी गई थी।

2. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात के खिलाफ जांच शुरू करने का निश्चय किया। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व भारत में ईयू का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत में यूरोपियन आयोग के प्रतिनिधिमंडल को, अन्य बातों के साथ-साथ, कथित पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का दावा करते हुए, आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित कर दिया था। प्राधिकारी ने कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी डिग्री और उसके प्रभाव का निर्धारण करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार संबंध देश में उत्पादित या उससे निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि वसूली जाए, घरेलू उद्योग को क्षति से बचाने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करते हुए भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 20 दिसंबर, 2010 को प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना सं0 14/39/2010 जारी की थी।
- ख. जांच में अपनाई गई प्रक्रिया
3. इस जांच के संबंध में अधोलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-

 - (क) उपर्युक्त नियमावली के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स गुजरात नर्मदा वैली फटिलाइजर्स कं0 लि (जीएनएफसी) द्वारा दायर लिखित आवेदन-पत्र प्राप्त किया जिसमें यूरोपियन यूनियन में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित एनिलिन के पाटन का आरोप लगाया गया था। मै0 हिन्दुस्तान आर्गनिक्स कैमिकल्स लि0 ने अभिव्यक्त रूप से इस याचिका का समर्थन किया।
 - (ख) प्राधिकारी ने जांच प्रारम्भ करने को न्यायोचित ठहराने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तुओं के आयात के विरुद्ध जांच प्रारम्भ करने का निश्चय किया है।
 - (ग) प्राधिकारी ने, जांच प्रारम्भ करने की प्रक्रिया से पूर्व, भारत में यूरोपियन कमीशन के प्रतिनिधिमंडल को पाटनरोधी नियमावली के उप-नियम 5(5) के अनुसार यह

अधिसूचित कर दिया कि सम्बद्ध भूभाग से सम्बद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की सूचना प्राप्त हुई है।

(घ) प्राधिकारी ने कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी डिग्री और उसके प्रभाव का निर्धारण करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(I) के अनुसार संबंध देश में उत्पादित या उससे निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि दसूली जांच घरेलू उद्योग को क्षति से बचाने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारेश करते हुए भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 20 दिसंबर, 2010 प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना सं 0 14/39/2010 जारी की थी। केन्द्र सरकार द्वारा जांच पूरी करने की तारीख बढ़ाकर 19 अप्रैल, 2012 कर दी गई थी।

(इ.) यह जांच, जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2009 से 30 जून, 2010 (15 माह) तक के लिए की गई थी। तथापि, क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच का आयोजन 2006-07, 2007-08, 2008-09 और जांच की अवधि के लिए किया गया।

(घ) प्राधिकारी ने सभी जात निर्यातकों, जिनके विवरण आवेदक ने उपलब्ध कराए थे और उद्योग एसोसिएशनों को सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अपने दृष्टिकोण लिखित रूप में भेजने के लिए अवसर प्रदान किया।

(छ) प्राधिकारी ने संबद्ध भू-भाग से संबद्ध वस्तु का भारत में आयात करने वाले सभी आयातकों को भी सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें पत्र जारी होने की तारीख से 40 दिनों के अन्दर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का सुझाव दिया।

(ज) प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति जात निर्यातकों और भारत में यूरोपियन कमीशन के प्रतिनिधिमंडल को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अन्तर्गत उपलब्ध कराई। आवेदन की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोध पर उपलब्ध कराई गई।

(ङ) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध भूभाग में जात निम्नलिखित निर्यातकों को प्रश्नावली भिजवाई जिसमें वे सूचना उपलब्ध करा सकें:

क्रम सं०	कंपनी का नाम
1.	बीएएसएफ एजी, जर्मनी
2.	हंट्समैन एडवांस्ड मैट्रियल्स, बेल्जियम
3.	हंट्समैन पैट्रोकेमिकल्स, यूनाइटेड किंगडम
4.	बोर्सोडकेम एमसीएचजेड, एस.आर.ओ., चेक गणराज्य
5.	मोरावास्के केमिकेजावोदी ओस्ट्रावा, चेक गणराज्य
6.	मै० बायर्स एजी, जर्मनी
7.	डोव केमिकल कंपनी, जर्मनी
8.	होचेस्ट एजी, जर्मनी

(ट) उपर्युक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में अधोलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया।

क्रम सं०	कंपनी का नाम
1.	ट्रेडकेम इंटरनेशनल एफजेडई, दुबई

(ठ) आयातक प्रश्नावलियाँ, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अन्तर्गत आवश्यक जानकारी मांगते हुए, भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित जात आयातकों/उपयोगकर्ताओं को भी भेजी गईः-

क्रम सं०	कंपनी का नाम
1.	आरती इंडस्ट्रीज लि०, मुंबई
2.	अबिर केमिकल्स लि०, अहमदाबाद
3.	एल्गिनेट्स एलाइड केमिकल्स प्रा० लि०, बादलपुर
4.	एल्फा डाईज एंड केमिकल्स, अहमदाबाद
5.	एसिएटिक कलर केम इंडस्ट्रीज, अहमदाबाद

6.	अतुल लिलो, गुजरात
7.	औरबिंदो फार्मा लिलो, हैदराबाद
8.	बायर्स इंडिया लिलो, मुंबई
9.	इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स ऐंड केमिकल्स लिलो, मुंबई
10.	इंटरनेशनल डाइस्ट्रीफ इंडस्ट्रीज, वडोदरा
11.	जय केमिकल इंडस्ट्रीज लिलो, अहमदाबाद
12.	मंगलम इंग्स ऐंड आर्गेनिक्स, मुंबई
13.	मैट्रोकेम इंडस्ट्रीज लिलो, अहमदाबाद
14.	नोसिल (एनओसीआईएल), मुंबई
15.	नूतन डाइकेम लिलो, मुंबई
16.	बेक (इंडिया) लिलो, पुणे
17.	भंगेरिया डाइकेम लिलो, मुंबई
18.	डायमंड डाइकेम, मुंबई
19.	गणेश केमिकल्स इंडस्ट्रीज, मुंबई
20.	हिन्दुस्तान इंक ऐंड रेज़िन लिलो, वारपी
21.	पदनासरा इंडस्ट्रीज लिलो, पदासारा
22.	रवि डाइवेयर कंपनी लिलो, मुंबई
23.	रूप डाइज ऐंड इंडस्ट्रीज
24.	स्केनेकटाडी बेक (इंडिया) लिलो, मुंबई
25.	सोनकमल इंटरप्राइज प्राप्ती लिलो, मुंबई
26.	विपुल डाइकेम लिलो, मुंबई

(ड) अधिसूचना के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित आयातकों/उपभोक्ताओं ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया:

- कच्छ केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिलो
- रवि डाइवेयर कंपनी लिलो
- बीएएसएफ इंडिया लिलो
- डाइस्ट्रीफ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन

- v. मै0 इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स एंड केमिकल्स (प्रा) लि
- vi. नोसिल (एनओसीआईएल) लि0

(छ) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सार्वजनिक फाइल के रूप में प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ को उपलब्ध कराया तथा इसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा।

(ष) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई जानकारी की गोपनीयता दावे का पालन करते हुए जांच की गई। प्राधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर यथा-वारेटेड गोपनीयता दावों को स्वीकार कर लिया गया और इस जानकारी को गोपनीय मान लिया गया तथा इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया गया।

(त) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांखियकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएडएस) से अनुरोध किया गया कि वह जांच की अवधि के दौरान और विगत तीन वर्षों के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयात का विवरण उपलब्ध कराएं।

(थ) आवेदक द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांत (जीएएपी) के आधार पर प्रस्तुत जानकारी के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं की अधिकतम उत्पादन लागत, उसे बनाने और उसकी बिक्री करने की लागत की गणना की गई ताकि यह निश्चय किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति से बचाने के लिए पर्याप्त होगा।

(द) प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को संगत जानकारी मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए 30 नवम्बर, 2011 को मौखिक सुनवाई का आयोजन किया। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले पक्षकारों को यह सुझाव दिया गया कि वे मौखिक रूप से प्रस्तुत जानकारी को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विचारों/जानकारी के संबंध में खंडनकारी तर्क/प्रत्युत्तर देने की अनुमति दी गई। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रस्तुतियों पर

उपयुक्त ढंग से विचार किया।

(ध) जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों और प्रदान कराई गई जानकारी, जो साक्ष्य द्वारा समर्थित थी और जिसे मौजूदा जांच के लिए संगत माना गया, पर, प्राधिकारी ने उपयुक्त ढंग से विचार किया।

(न) सुप्रा नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचारित अनिवार्य तथ्यों/आधारों को दिनांक 20 मार्च, 2012 के प्रकटन विवरण के तहत हितबद्ध पक्षकारों की जानकारी के लिए प्रकट कर दिया गया और उन पर प्राप्त टिप्पणियों को, जिन्हें प्राधिकारी ने संगत माना, का अपनी अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना में निराकरण कर दिया।

(म) *** इस अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना में आवेदक द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत कराई गई जानकारी और नियमावली के अन्तर्गत प्राधिकारी द्वारा विचार की गई जानकारी को शामिल किया गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

4. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:-

(क) एनिलिन को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अन्तर्गत सीमाशुल्क उप शीर्षक सं0 2921.41 के अन्तर्गत कार्बनिक रसायनों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(ख) एनिलिन एक पारदर्शी, तैलीय तरल पदार्थ है और यह प्राथमिकतः एमाइन संयोजक है। इसे जब डिस्टिल्ड किया जाता है तो यह हल्के पीले रंग के तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। रोशनी या हवा में रखे जाने पर इसका रंग गहरा हो जाता है। एनिलिन एक बेसिक कार्बनिक रसायन है और यह ड्रग्स, फार्मास्युटिकल्स, रंग और रंजक मध्यवर्तियों आदि जैसे बड़े उद्योगों में अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है। एनिलिन को रबड़ रसायनों, विस्फोटकों, रेजिन आदि जैसे कुछ अन्य उद्योगों में भी प्रयोग में लाया जाता है। एनिलिन का

उत्पादन करने के लिए बेन्जीन, हाइड्रोजन और संकेन्द्रित नाइट्रिक अम्ल प्रमुख कच्चा माल हैं। नाइट्रोवैजिन जो एनिलिन का उत्पादन करने के लिए एक मध्यवर्ती, का उत्पादन बेन्जीन का नाइट्रेशन करके किया जाता है। तत्पश्चात् नाइट्रोबेन्जीन का हाइड्रोजन के साथ कैटलिटिक रिडेक्शन करके एनिलिन का उत्पादन किया जाता है।

(ग) एनिलिन का प्रयोग बल्कनाइजेशन एजेंट, एक्सिलिरेटर और एंटी-ऑक्सीडेंट के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग फोटोग्राफिक रसायनों, रंग और रंजक मध्यवर्तियों, फार्मास्युटिकल्स, आइसोसाइन्सहस्त्रस में किया जाता है। एनिलिन का प्रयोग विस्फोटकों, पेस्टीसाइड्स, कीटनाशकों, हर्बिसाइड्स कवकरोधी आदि कर उत्पादन करने में भी किया जाता है। संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अन्तर्गत सीमाशुल्क उप-शीर्षक संख्या 2921.41 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतक है और यह मौजूदा जांच के दायरे में बाध्यकारी नहीं है।

(घ) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एनिलिन और संबद्ध देश से निर्यातित एनिलिन में कोई फर्क नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एनिलिन और संबद्ध देश से आयातित एनिलिन की तुलना भौतिक और रासायनिक गुणविशेषों, विनिर्माण प्रक्रिया और तकनीक(पूरे विश्व में उत्पादकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली), कार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और टैरिफ वर्गीकरण के रूप में की जा सकती हैं। दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता लोग इन दोनों का विनिमय करते हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित एनिलिन और संबद्ध देशों से आयातित एनिलिन समान वस्तु हैं।

ग.2 आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने याचिकाकर्ता के इस दावे का विरोध नहीं किया कि संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु और इस देश में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेची जा रही वस्तु, दोनों समान वस्तुएँ हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित जांच की गई:

क. प्रस्तुत जांच में विचाराधीन उत्पाद एनिलिन है जिसे “एनिलिन ऑयल” के रूप में भी जाना जाता है और जो यूरोपियन यूनियन में उत्पादित या वहां से निर्यात किया जाता है। एनिलिन एक पारदर्शी, तेलीय तरल पदार्थ है और यह प्राथमिकतः एमाइन संयोजक है। इसे जब डिस्ट्रिल्ड किया जाता है तो यह हल्के पीले रंग के तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। रोशनी या हवा में रखे जाने पर इसका रंग गहरा हो जाता है। एनिलिन एक बेसिक कार्बनिक रसायन है और यह इंग्स, फार्मास्युटिकल्स, रंग और रंजक मध्यवर्तियों आदि जैसे बड़े उद्योगों में अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है। एनिलिन को रबड़ रसायनों, विस्फोटकों, रेजिन आदि जैसे कुछ अन्य उद्योगों में भी प्रयोग में लाया जाता है। एनिलिन को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अन्तर्गत सीमाशुल्क उप-शीर्षक संख्या 2921.41 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतक है और यह मौजूदा जांच के दायरे में बाध्यकारी नहीं है। इस जानकारी को विदेशी उत्पदकों द्वारा अपने प्रत्युत्तर में प्रदान कराई गई जानकारी से संबद्ध किया गया है।

ख. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(घ) यह स्पष्ट करता है कि समान वस्तु का आशय, ऐसी वस्तु से है जो विचाराधीन उत्पाद के बारे में सभी तरह से समान और आइडेंटिकल हो अथवा ऐसी वस्तु की अनुपस्थिति में कोई अन्य वस्तु जिसका गुणधर्म जांचाधीन वस्तु के समान हो, से है।

ग. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश में उत्पादित या निर्यातित वस्तु दोनों समान वस्तुएं हैं। विरोधकर्ता किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की। प्राधिकारी यह नोट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एनिलिन के गुणधर्म संबद्ध देश से आयातित एनिलिन के गुणधर्म के समान हैं।

घ. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी धारित करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक गुण विशेष, विनिर्माण प्रक्रिया और तकनीक, इसके कार्य एवं प्रयोग, उत्पादन विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण

के रूप में समान वस्तु है। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 29 के अन्तर्गत उप शीर्षक संख्या 2921.41 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है परन्तु सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है और यह वर्तमान जांच के दायरे के लिए बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकर्ता के विचार

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

7. घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में, घरेलू उद्योग के निम्नलिखित विचार हैं:

- क. यह याचिका मैसर्स गुजरात नर्मदा वैली फटिलाइजर्स कंपनी द्वारा दायर की गई है। मैरी हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं जिससे उन्होंने अभिव्यक्त रूप से इस याचिका का समर्थन किया है। भारत में दो अन्य कंपनियां भी हैं जिन्होंने एनिलिन का उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त कर ली है, उनके नाम हैं मैसर्स एनिरॉक्स पिमेंट्स लिमिटेड और मैरी लुना कैमिकल्स लिमिटेड।
- ख. याचिकाकर्ता तथा एचओसीएल का उत्पादन भारतीय उत्पादन का प्रमुख अनुपात बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता को नियमावली के आशय के अन्तर्गत “घरेलू उद्योग” के रूप में माना जाए।
- ग. मैक्सिको, स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स, ग्वाटेमाला से संबंधित मामले में डब्ल्यूटीओ रिपोर्ट संबंधी आयातकों/उपभोक्ताओं/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार अनुचित हैं। इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियाँ पूरी तरह से भिन्न हैं।
- घ. उक्त जांच में जांचकर्ता प्राधिकारी ने उत्पादकों को घरेलू उद्योग के रूप में निर्धारित किया है जो संबंधित उत्पाद का 88% उत्पादन करते हैं जबकि उत्पादकों के लिए क्षति की जांच संबंधित उत्पाद के 53% के बारे में की गई है।
- ड. वस्तुतः उक्त निर्णय में डब्ल्यूटीओ ने यह धारित किया है कि व्यवहार में जांचकर्ता प्राधिकारी को जांच शुरू करने के लिए आंशिक जानकारी दी जा सकती

है जिसे बाद में जांच प्रक्रिया के रूप में पूरी की जा सकती है।

च. वर्तमान मामले के तथ्यों में गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कं0 लि0 ने याचिका दायर की जिसका हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि0 द्वारा समर्थन किया गया। इस तथ्य का जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लेख किया गया।

घ.2 आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

8. अपने आधार के संबंध में आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नलिखित हैं:-

क. याचिका में एचओसीएल का नाम नहीं है और इसलिए एचओसीएल जांच प्रारंभ अधिसूचना में घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं बन सकता।

ख. एचओसीएल के आंकड़ों को घरेलू उद्योग के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि जांच प्रारंभ अधिसूचना में उल्लेख है कि आवेदक को घरेलू उद्योग होना चाहिए जो इस मामले में गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कं0 लि0 है।

ग. जांच के प्रारंभ घरेलू उद्योग का निर्धारण किया जाता है और यह संपूर्ण जांच-अवधि के दौरान जारी रहना चाहिए और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मैकिसको पाटनरोधी शुल्क – ग्वाटेमाला से स्टील पाइप्स और ट्यूब्स के मामले में डब्ल्यूटीओ के निर्णय में रिलायंस को रखा गया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. दिनांक 1.12.2011 को यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के के अन्तर्गत घरेलू उद्योग को निम्नवत परिभाषित किया गया है:

“(ख) “घरेलू उद्योग” का आशय समग्र रूप से ऐसे घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबंधित किसी क्रियाक्रलाप में लगे हों अथवा उक्त वस्तु का उनका सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता हो परन्तु जब ये उत्पादक कथित पाइत वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा उसके स्वयं आयातक हों तो

ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' को शेष उत्पादकों के स्पष्ट में उल्लिखित किया जाएगा।"

10. यह याचिका मैसर्स गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी द्वारा दायर की गई है। भारत में संबद्ध वस्तु के केवल तीन अन्य जात उत्पादक हैं अर्थात् मैरी हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, एनिरॉक्स पिग्मेंट्स लिमिटेड और लूना कैमिकल्स लिमिटेड। मैरी हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड ने अभिव्यक्त रूप से इस याचिका का समर्थन किया है और इस बारे में उन्होंने समस्त संगत जानकारी प्राधिकारी को दी है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मैरी एनिरॉक्स पिग्मेंट्स लिमिटेड ने अपना उत्पादन बंद कर दिया है। आवेदन में प्रदान कराई गई सूचना के अनुसार गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड और एचओसीएल का उत्पादन जाँच की अवधि के दौरान कुल भारतीय उत्पादन का "एक प्रमुख हिस्सा" बनता है।
11. इसलिए प्राधिकारी यह नोट करता है कि याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5 (3) (क) के आशय के अन्तर्गत घरेलू उद्योग बनते हैं।
12. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दावा किया गया कि जीएनएफसी द्वारा याचिका दायर की गई है और उनकी याचिका के आधार पर प्राधिकारी ने जाँच शुरू कर दी। अतः, तदुपरान्त, घरेलू उद्योग के संघटन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता और प्राधिकारी जाँच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित घरेलू उद्योग के आधार पर जाँच प्रक्रिया का पालन करेगा। इसलिए, एचओसीएल को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस संबंध में गवाटेमाला से स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स संबंधी मैक्रिस्को – पाटनरोधी शुल्क से संबंधित मामले में डब्ल्यूटीओ के निर्णय का उल्लेख किया गया है और यह दावा किया गया है कि डब्ल्यूटीओ ने यह धारित किया है कि जाँचकर्ता प्राधिकारी को घरेलू उत्पादकों, जिन्होंने शुरुआती स्तर पर याचिका का समर्थन किया है, से सूचना मांगने और उन सूचनाओं का विश्लेषण के लिए प्रयोग करने से मना नहीं किया गया है।
13. उपर्युक्त के संदर्भ में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार द्वारा उल्लिखित गवाटेमाला से स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स संबंधी मैक्रिस्को – पाटनरोधी शुल्क से संबंधित मामले में डब्ल्यूटीओ निर्णय में यह उल्लेख नहीं है कि जाँचकर्ता प्राधिकारी को घरेलू उत्पादकों, जिन्होंने शुरुआती स्तर पर याचिका का समर्थन किया है, से सूचना मांगने और उन सूचनाओं का विश्लेषण के लिए प्रयोग करने से मना नहीं किया गया है।

अन्य मुद्दे

14. घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दे

क. घरेलू उद्योग ने पूर्व-व्यापी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने का अनुरोध किया है क्योंकि पाटन का एक लम्बा इतिहास है।

ख. इसे संबद्ध वस्तुओं के पाटन संबंधी विगत रिकॉर्ड और उत्तरवर्ती पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण से देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका से पाटन, जिसके कारण पाटनरोधी शुल्क लगाया गया (जिसे पांच वर्षों की और अवधि के लिए बढ़ाया गया था) उत्पाद के पाटन को स्थापित करता है।

ग. इसके अतिरिक्त, निर्यातकों द्वारा सहयोग न किए जाने से यह स्पष्ट होता है कि वे पाटन का सहारा ले रहे हैं। आयातक भी पाटन प्रक्रियाओं से अच्छी तरह से अवगत हैं।

15. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे

क. समानांतर जांच अर्थात् मौजूदा जाँच और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जापान से आयातों की सन-सेट पुनरीक्षा जाँच के लिए समान जाँच अवधि ली जाए जैसाकि विगत में निर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा किया गया है।

ख. अत्यधिक गोपनीयता: याचिकाकर्ताओं ने पाटनरोधी आवेदन प्रपत्र के अन्तर्गत फार्मेट के से ड., सामान्य मूल्य परिकलन करने के लिए अन्य व्यय उप-शीर्षों तथा भाड़ा स्रोतों, याचिकाकर्ता तथा अन्य उत्पादकों के बाजार हिस्से, प्रश्न 14 ख में यथाअपेक्षित बिक्री नीति विवरण तथा प्रपत्र IVक द्वारा यथाअपेक्षित कीमत कटौती का खुलासा नहीं किया है।

ग. क्षति विश्लेषण के लिए एचओसीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी/ केवल 10 महीने के आंकड़ों के पश्चात् के आंकड़ों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

घ. गोपनीयता के अन्तर्गत सामान्य मूल्य के यथार्थ परिकलन को छुपाया गया है जिससे कि किसी टिप्पणी से बचा जा सके।

इ. याचिका में उपलब्ध कराए गए लेन-देन बार आयात आंकड़े उन आंकड़ों से भिन्न हैं जिन पर क्षति विश्लेषण में विचार किया गया।

ज. प्राधिकारी जाँच प्रारंभ करने से पहले आंकड़ों की सच्चाई और उपयुक्तता की पहचान करने में असफल रहे।

छ. संबंधित वस्तु की बीजक तारीख और पोत लदान की तारीख में पर्याप्त अंतर है जिसके कारण पहुँच मूल्य और घरेलू कीमतों में विकृति आना बाध्यकारी है।

ज. आयातित वस्तुओं के लैंडेड मूल्य का निर्धारण करने के लिए निर्यात कीमत का परिकलन बीजक तारीख में प्रदर्शित कीमत के आधार पर किया जाता है। इसलिए, लैंडेड मूल्य के साथ तुलना की जा रही घरेलू बिक्री कीमत को बीजक तारीख में समरूप समयावधि से संबंधित होना चाहिए और न कि संबद्ध वस्तुओं की पोत लदान किए जाने के समय प्रचलित घरेलू कीमतों से।

झ. इसके वित्तपरीत, यदि घरेलू उद्योग की कीमतों पर उस तारीख को विचार किया जाता है जिस तारीख को संबद्ध वस्तुओं का आयात किया गया तो ये घरेलू कीमतें उस उत्तरवर्ती समय पर आधारित होनी चाहिए जब बीजक की तारीख पर प्रचलित कीमतों से भिन्न कीमतें प्रचलन में हों।

ट. याचिकाकर्ताओं का यह अनुरोध न्यायोचित नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पूर्वव्यापी रूप से लगाया जाए क्योंकि अधिनियम की धारा 9क (3) में यथानिर्धारित, शुल्क अधिरोपण के लिए दो अनिवार्य पूर्व शर्तों अर्थात् (i) पाटन का इतिहास और (ii) अल्प समयावधि में भारी पाटन तथा इससे हुई क्षति इतनी गंभीर है कि यह पाटनरोधी शुल्क के उपचारी प्रभाव को कम कर देगी, को पूरा नहीं किया गया।

ठ. यूएसए और यूरोप में सामान्य उत्पादकों का दावा गलत है और यह बिना किसी साक्ष्य के है।

ड. जाँच की अवधि गलत है क्योंकि यह मामला दिसंबर, 2010 में पाँच माह में जाँच अवधि समाप्त होने के साथ शुरू किया गया था। जाँच अवधि के रूप में बारह महीने लेने और वर्तमान मामले में जाँच अवधि में 15 महीने लेने के

सामान्य नियम से विपर्यन का कोई कारण नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त, जाँच अवधि का निर्धारण करते समय आर्थिक मन्दी पर भी विचार नहीं किया गया।

३. समान संबद्ध वस्तु पर एक ही समय पर शुरू की गई दो जाँचों में दो पृथक जाँच-अवधि बिना किसी औचित्य के बनाई गई हैं। याचिकाकर्ता मुद्दे को विपरित करने का प्रयास कर रहा है जोकि यह है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी में० एचओसीएल को किसी पक्षकार द्वारा अनुरोध किए बिना समर्थक के रूप में मान ले। जाँच शुरूआत अधिसूचना पक्षकारा द्वारा दिए गए आवेदन, जिसके साथ में सभी दस्तावेज लगे हुए थे और जिसमें इस शुरूआत की मांग की गई थी, का परिणाम है और न कि इसके विपरीत।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

16. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता दावों की जाँच की। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में आवेदन में गोपनीयता का दावा प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुरूप है। हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के अनुचित दावे के किसी विशिष्ट उदाहरणों को स्थापित नहीं किया है। प्राधिकारी ने उस जानकारी के संबंध में गोपनीयता के दावे की अनुमति दे दी है जो प्राकृतिक रूप से गोपनीय है क्योंकि इसका खुलासा करने से प्रतिस्पर्धी को अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा और इसका खुलासा करने से जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति पर जहाँ से वह जानकारी प्राप्त हुई है, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी ने गोपनीय जानकारी प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से उनका अगोपनीय सार देने की अपेक्षा की है इसलिए, गोपनीयता के दावे से संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने इसकी अनुमति दे दी।

17. संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में सामान्य उत्पादकों के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कुछ ऐसे उत्पादक हैं जिनकी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में समान रूप से उत्पादन सुविधाएं मौजूद हैं। एचओसीएल के समर्थन के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एचओसीएल द्वारा समर्थन के तथ्य का जाँच शुरूआत अधिसूचना में उल्लेख किया गया है। इसलिए, इस तर्क में कोई वजन नहीं है। प्राधिकारी

कों प्रक्रियाओं के प्रत्येक स्तर पर घरेलू उद्योग के दायरे का निर्धारण करना होता है। वस्तुतः जॉच की शुरुआत करने का एक उद्देश्य सभी संगत पक्षकारों से संगत जानकारी मंगाना भी होता है और यदि जॉच प्रारंभ होने के पश्चात् कोई एक या अधिक अन्य घरेलू उत्पादक प्राधिकारी के समक्ष कोई सूचना प्रस्तुत करते हैं तो प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे क्षति का आकलन करने के उद्देश्य से इस सूचना को शामिल करें। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी जॉच एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ जांच में प्रगति के साथ-साथ साक्ष्य की गुणवत्ता एवं मात्रा में सुधार होता है।

ड. प्राटन मार्जिन का निर्धारण

18. घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दे

- क. याचिकाकर्ता न तो यूरोपियन यूनियन की घरेलू बाजार में कीमत के संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त कर सका और न ही ईयू से तीसरे देशों को निर्यात कीमत के लिए अधिप्रापण का कोई साक्ष्य देने में सक्षम हो सका।
- ख. सामान्य मूल्य का निर्धारण ईयू से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए किया गया है।
- ग. समयावधि के साथ-साथ लागत और कीमतों में महत्वपूर्ण अन्तर के मद्देनजर, सामान्य कीमत का निर्धारण विविध औसतों पर विचार करके किया गया।
- घ. निर्यात कीमत का निर्धारण जॉच की अवधि के दौरान गौण औसत अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस सूचना सेवा मुंबई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आयातों की मात्रा और कीमत पर विचार करते हुए किया गया। समयावधि के साथ कीमतों में महत्वपूर्ण भिन्नता पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता ने जॉच अवधि के प्रत्येक माह के लिए अलग निर्यात कीमतों का निर्धारण किया है।

19. भारत में आयातकों, उपभोक्ताओं सहित अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे

- क. याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य का निर्धारण तृतीय देशों को निर्यात पर विचार किए बिना कर लिया। तृतीय देशों को निर्यात से संबंधित उक्त जानकारी से यह स्पष्ट है कि कुल औसत निर्यात कीमत भारत को निर्यातित विचाराधीन उत्पाद की कीमत से बहुत कम है।

ख. भारत को निर्यात उन कीमतों पर किए जाते हैं जो इंडोनेशिया जैसे विकासशील देशों को किए जाने वाले निर्यात कीमत से तुलनीय हैं और वस्तुतः मैक्रिस्को, रूस और दक्षिण अफ्रीका जैसी अन्य अर्थव्यवस्थाओं की कीमतों से उच्चतर हैं, इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि जॉच-अवधि में विचाराधीन उत्पाद का पाटन नहीं हुआ।

ग. ईयू संबद्ध वस्तु का निर्यात 875 यूरो/मी.टन के भारित औसत कीमत पर अन्य देशों को भी करता रहा है और साथ ही इसने 936 यूरो, मी.टन पर भारत को भी निर्यात किया जिससे किसी भी दृष्टिकोण से पाटन का निष्कर्ष नहीं निकलता है। भारत को निर्यात, उन कीमतों पर किए गए जो विकासशील देशों से तुलनीय हैं।

घ. उत्पादन लागत का निर्धारण करने के लिए ऑकड़ों को बेन्जीन के मासिक कीमत निर्धारण के आधार पर तैयार किया गया जिससे एनवी का परिकलन होता है और उसकी समान निर्यात कीमत से तुलना की गई परन्तु क्षति का विश्लेषण करते समय इस मानदंड को नहीं अपनाया गया। इसलिए, अपनाई गई पद्धति को अस्वीकार कर देना चाहिए।

ड. कानून के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ये कहता हो कि व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का निर्धारण केवल तभी किया जा सकता है जब संबंधित निर्यातक और उत्पादक दोनों ही जॉच में सहयोग करें और इसके अभाव में आत्मनिवेदनों को अस्वीकार किया जा सकता है। नियम 17(3) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार प्रत्येक जात निर्यातक या उत्पादक का निर्धारण करने के लिए पाटन मार्जिन की पृथक-पृथक दर की अपेक्षा होती है। धारा 9क (6क) में 'उत्पादकों या निर्यातकों' के वाक्यांशों का भी प्रयोग किया जाता है। ट्रेडकेम एक जात निर्यातक है और उनके लिए पृथक से पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जाना चाहिए।

च. विगत में डीजीएडी मामलों अर्थात् चीन से 8-हाइओॉक्सीक्यूनोलिन, ईयू से एसिटोन, चाइनीज टाइपेई, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका; सिल्क फैब्रिक्स, फिनॉल में डीजीएडी ने उत्पादक द्वारा उत्तर न दिए जाने के बावजूद भी निर्यात(व्यापारी) के लिए पृथक दर का निर्धारण किया। कार्बन ब्लैक के मामले में व्यापारी के लिए पृथक पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया था, हालांकि इसने पूरी तरह से अपना सहयोग नहीं दिया था।

छ. ट्रेडकेम द्वारा प्रस्तुत निर्यात कीमत संबंधी सूचना को नामंजूर किया जा सकता है जैसाकि भारत से यूएस-स्टील प्लेट के मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल ने किया।

ज. उपलब्ध तथ्य ट्रेडकेम पर लागू नहीं होने चाहिएं क्योंकि इसने डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 6.8 का उल्लंघन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, अनुबंध II के पैरा 3 में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा किया गया है। इसलिए निर्यातक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को शामिल न करने का कोई आधार नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

20. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दुबई के व्यापारी ट्रेडकेम ने प्रत्युत्तर दिया है और व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का दावा किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि व्यापारी ने अपने प्रत्युत्तर में उल्लेख किया है कि कंपनी यूरोप सहित कई देशों से एनिलिन खरीदती है और इसकी भारतीय ग्राहकों को बिक्री करती है। पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी को सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की जरूरत होती है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि यूरोपियन यूनियन से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला है। यूरोपियन यूनियन के उत्पादकों से प्रत्युत्तर के अभाव में प्राधिकारी फैक्टरी बाह्य स्तर निर्यात कीमत का सामान्य मूल्य से तुलना करने के लिए निर्धारण नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए केवल सीआईएफ निर्यात कीमत ही पर्याप्त नहीं है। विगत के अन्य मामलों के संदर्भ में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन मामलों का संदर्भ अनुचित है और इन मामलों के तथ्य एवं परिस्थितियाँ वर्तमान मामले से भिन्न हैं।

21. तृतीय देशों को निर्यातों के अनुरूप सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में सामान्य मूल्य के दावे का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्धारण से प्रथम दृष्टया भिन्न है। अंतिम निर्धारण के लिए प्राधिकारी को घरेलू बिक्री अर्थात् व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में, के संबंध में सत्यापन योग्य जानकारी की जरूरत होती है जो इस मामले में उपलब्ध नहीं है क्योंकि किसी श्री निर्यातक/उत्पादक ने प्राधिकारी के साथ सहयोग करने को अधिमानता नहीं दी है।

ड.1 सामान्य मूल्य

29. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9क(1)(ग) के अन्तर्गत किसी वस्तु के संबंध में 'सामान्य मूल्य' का आशय है:

(i) उपधारा(6) के अन्तर्गत बने नियम के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातकर्ता देश या भूभाग में खपत के आशय से समान मद के लिए, व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में, तुलनीय कीमत; अथवा

(ii) जब निर्यातकर्ता देश या भूभाग की घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान मद की बिक्री न हो या निर्यातकर्ता देश या भूभाग की घरेलू बाजार में विशेष बाजार स्थितियों या बिक्री की न्यून मात्रा के कारण ऐसी बिक्रियाँ सामान्य तुलना की अनुमति नहीं देती हैं तो सामान्य मूल्य या तो -

(क) उप धारा (6) के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातकर्ता देश या भूभाग या एक उपयुक्त तृतीय देश से निर्यातित समान मद की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत होगी; या

(ख) उप धारा (6) के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत तथा लाभ को तर्क संगत ढंग से जोड़ते हुए उद्गम के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।

जब संबद्ध वस्तु का आयात उद्गम के देश के अलावा किसी अन्य देश से किया जाता है तो ऐसे आयात के मामले में और जहां इस वस्तु को निर्यात के देश के जरिए केवल जहाज़ द्वारा लाया गया है या ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है या निर्यात के देश में उस वस्तु की कोई तुलनीय कीमत नहीं है तो सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम के देश में इसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

29. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के संबद्ध देश स्थित किसी उत्पादक या निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया है। मैं 0 ट्रेडकेम इंटरनेशनल एफजेडई, दुबई द्वारा ही प्रत्युत्तर दायर किया गया है। यह नोट किया जाता है कि कम्पनी एक ऐसा व्यापारी है जो संबद्ध वस्तु को यूरोपियन यूनियन सहित विभिन्न देशों

से जुटाती है और भारत को इसका निर्यात करती है। इसके अतिरिक्त, यूरोपियन यूनियन से किसी ऐसे उत्पादक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है जिसकी संबद्ध वस्तु का निर्यात ट्रेडकेम इंटरनेशनल एफजेडई, दुबई द्वारा किया गया है। अतः लेन-देन की निर्यात शृंखला पूरी नहीं है और इस प्रकार प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ट्रेडकेम इंटरनेशनल एफजेडई, दुबई द्वारा प्रस्तुत जानकारी को विचार में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करते हैं।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की संबद्ध देश की घरेलू बाजार में कीमतों के संबंध में सूचना/साक्ष्य का अधिप्रापण याचिकाकर्ता द्वारा नहीं किया जा सका क्योंकि सार्वजनिक रूप से कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता यूरोप से तृतीय देशों को निर्यात कीमत के संबंध में जानकारी एकत्र नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त, यूरोप से तृतीय देशों को माहवार निर्यातों के संबंध में किसी प्रकाशित जानकारी के अभाव में तृतीय देशों को निर्यात की मात्रा को न्यून करके नहीं विचारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत, प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत का विवरण अनुपलब्ध होने की स्थिति में प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि क्या तृतीय देशों को निर्यात व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में किए गए थे या नहीं।

इसलिए संबद्ध देश में सामान्य मूल्य का निर्धारण निर्मित मूल्य पर विचार करते हुए किया गया।

24. ईयू से आयातित एनिलिन के सामान्य मूल्य का निर्माण निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर किया गया:

- (क) सर्वाधिक कुशल घरेलू उत्पादक द्वारा प्रमुख कच्चे माल बेन्जीन, सीएनए और हाइड्रोजन के सर्वोत्तम उपयोग मानदंडों पर विचार किया गया।
- (ख) आईसीआईएस एलओआर(यूरोप) द्वारा प्रकाशित औसत कीमत के आधार पर जॉच की अवधि के दौरान बेन्जीन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया गया। हाइड्रोजन और सीएनए की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अभाव में कुशल उत्पादकों की दर को स्वीकार किया गया। अन्य छोटे-छोटे कच्चे माल की लागत का निर्धारण

सर्वाधिक कुशल घरेलू उत्पादक की लागत के अनुसार विचार करते हुए, किया गया।

(ग) उपयोगों की लागत, परिवर्तन लागत, एसजीए व्यय और हित के संबंध में सर्वाधिक कुशल घरेलू उत्पादक के स्तर से विचार किया गया।

(ज) तर्क संगत लाभ के लिए, ब्याज को छोड़कर बिक्रियों की 5% लागत की अनुमति दी गई है।

तद्वारा यूरोपियन यूनियन से एनिलिन की भारित औसत सामान्य कीमत 1.20 अमरीकी डॉलर प्रति किलो. निर्धारित की जाती है।

ड.2 निर्यात कीमत

25. किसी वस्तु के संबंध में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9क(1)(ख) के अन्तर्गत 'निर्यात कीमत' का आशय है

(ख) किसी वस्तु के संबंध में "निर्यात कीमत" का आशय निर्यातकर्ता देश या भूभाग से निर्यातित मद की कीमत और ऐसे मामलों में जहाँ निर्यात कीमत नहीं है या जहाँ निर्यातक और आयातक या तृतीय देश के बीच प्रतिपूरक व्यवस्था या संगम के कारण निर्यात कीमत अविश्वसनीय है, वहाँ निर्यात कीमत का निर्धारण उस कीमत के आधार पर किया जा सकता है जिस पर आयातित वस्तुओं की किसी स्वतंत्र क्रेता को प्रथम पुनर्बिंक्री की गई कीमत या यदि वस्तु की पुनर्बिंक्री स्वतंत्र क्रेता को नहीं की गई या उन शर्तों पर पुनर्बिंक्री नहीं की गई जिन शर्तों पर उनका आयात किया गया था, वहाँ निर्यात कीमत का निर्धारण उप-धारा 6 के अन्तर्गत बने नियम के अनुरूप तर्कसंगत आधार पर किया जा सकता है।

26. संबद्ध वस्तु के संबद्ध देश में किसी निर्यातक/उत्पादक द्वारा उत्तर न मिलने के मद्देनजर निर्यात कीमत का निर्धारण जाँच की अवधि के लिए डीजीसीआईएस आंकड़ों के अनुसार आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए किया जाता है। समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, इनलैण्ड भाड़ा और बैंक प्रभार के कारण समायोजन किया गया है। इस प्रकार निर्यात कीमत 1.02 अमरीकी डॉलर प्रति किलो. निर्धारित की जाती

है।

ड.3 पाटन मार्जिन

27. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1)(क) के अन्तर्गत 'पाटन मार्जिन' का निर्धारण निम्नवत किया जाता है:

(क) किसी वस्तु के संबंध में "पाटन के मार्जिन" का आशय निर्यात कीमत और इसके सामान्य मूल्य के बीच अंतर से है।

28. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना करने के संबंध में नियम में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"पाटन के मार्जिन का निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेगा। व्यापार के समान स्तर, सामान्यतः कार्य-बाह्य स्तर और लगभग यथा संभव उसी समय पर की गई बिक्री के बारे में तुलना करेगा। प्रत्येक मामले में गुणवत्ता आधार पर शर्तों और बिक्रियों में अंतर, कर निर्धारण, व्यापार की मात्रा के स्तर, भौतिक विशेषताओं और अन्य विभिन्नताओं जो कीमत तुलनात्मकता को प्रभावित करती हुई प्रतीत होती हैं, सहित घटित होने वाली कीमत तुलनात्मकता के अन्तर पर उचित ढंग से विचार किया जाएगा।"

29. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना करने के उद्देश्य से प्राधिकारी, याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और प्राधिकारी के पास उपलब्ध अन्य प्रकाशित जानकारी पर विचार करते हैं। ऊपर वर्णित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत कार्य-बाह्य स्तर पर हैं। पाटन मार्जिन अधोलिखित तालिका में दिया गया है:-

स्रोत	सामान्य कीमत अमरीकी डालर/किग्रा.	निर्यात कीमत अमरीकी डालर/किग्रा	पाटन मार्जिन अमरीकी डालर/किग्रा	पाटन मार्जिन %
यूरोपियन यूनियन - सभी उत्पादक एवं	***	***	***	15-25

नियातक				
--------	--	--	--	--

30. इस तरह निर्धारित पाटन मार्जिन काफी महत्वपूर्ण हैं और न्यूनतम स्तर से ऊपर हैं।

च. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध की जाँच

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रस्तुतीकरण

31. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतीकरण किया गया:

- 1) वर्ष 2008-09 को छोड़कर संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। मांग में इस कमी के पीछे का कारण वैश्विक मंदी की स्थिति है।
- 2) घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। जाँच की अवधि के दौरान बिक्री की मात्रा में अल्प वृद्धि वैश्विक मंदी के पश्चात हुए सुधार के कारण आई।
- 3) संबद्ध देश से आयातों में समग्र रूप में और भारत में कुल आयातों के संबंध में वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयातों में भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के संबंध में वृद्धि हुई है।
- 4) संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में, विशेष रूप से जाँच अवधि के दौरान, अत्यधिक वृद्धि प्रदर्शित हुई है जहां यह आधार वर्ष की तुलना में तीन गुना बढ़ गई और घरेलू उद्योग में कमी प्रदर्शित हुई है। संबद्ध देश ने घरेलू उद्योग के हिस्से पर कब्जा कर लिया।
- 5) संबद्ध देश से आयातों के कारण भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है। इस प्रकार आयातों से बाजार में कीमत में हास आ रहा है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हुई है जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है। इस प्रकार, आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत का हनन हुआ।
- 6) घरेलू उद्योग द्वारा अपनी क्षमता स्थिर बनाए रखने के बावजूद घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई। घरेलू उद्योग के उत्पादन में, आयातों में वृद्धि के कारण, बिक्री कम होने के कारण गिरावट आई।

- 7) घरेलू उद्योग के लाभ में अत्यधिक कमी हुई। बिक्री कीमत में वृद्धि या कमी लागत के आनुपातिक नहीं है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभदायकता का अत्यधिक हास हुआ।
- 8) लाभदायकता में गिरावट के कारण निवेश से आय और नकदी प्रवाह के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई।
- 9) जॉच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की माल सूची में विगत वर्षों की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई।
- 10) घरेलू उद्योग को अधिकांश क्षति मापदंडों के अनुरूप नकारात्मक वृद्धि का सामना करना पड़ा है।
- 11) घरेलू उद्योग द्वारा अपने उत्पाद न्यूनतम कीमत पर प्रस्तुत किए जाने के बावजूद, इसकी बिक्री में गिरावट हो रही है।
12. चूंकि, संबद्ध वस्तु के बारे में पाटन का लम्बा इतिहास है, इसलिए आवेदक ने पूर्वव्यापी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने का अनुरोध किया है। इसको संबद्ध वस्तु के पाटन संबंधी विगत रिकॉर्ड और तदुपरान्त पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने से देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका से पाटन, जिसके कारण पाटनरोधी शुल्क लगाया गया (जिसे 5 वर्षों की अवधि के लिए पुनः बढ़ाया गया) उत्पाद के पाटन को पुनः स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त, निर्यातकों द्वारा सहयोग न करने से यह सिद्ध होता है कि वे पाटन कर रहे हैं। आयातक भी इस पाटन व्यवहार से अच्छी तरह से अवगत हैं।
13. घरेलू उद्योग द्वारा अपने उत्पाद न्यूनतर कीमत पर प्रस्तुत किए जाने के बावजूद, इसकी बिक्री में गिरावट आ रही है।
14. व्यापारी के माध्यम से बिक्री किए जाने के आग्रह के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग अपने माल की प्रत्यक्ष एवं व्यापारी के ज़रिए बिक्री करता है और ये उपभोक्ता पर निर्भर करता है कि वे सामान को किस स्रोत से खरीदने का निश्चय करते हैं।

च. 2 आयातकों और उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे

32. आयातकों और उपयोगकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतीकरण किया गया:

- 1) याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्रियाँ मध्यवर्ती व्यापारी अर्थात् ट्रेडेक्स कारपोरेशन द्वारा की जाती हैं। याचिकाकर्ता द्वारा अपने उत्पाद की बिक्री कीमत घरेलू उद्योग की कीमत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है क्योंकि यह वह कीमत नहीं है जिस पर अंतिम उपभोक्ता विचाराधीन उत्पाद की खरीद करता है।
- 2) यद्यपि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है परन्तु भूभाग में कुल आयात की मात्रा वही बनी रही।
- 3) अवधि के दौरान कीमतों में कोई कटौती नहीं हुई। वास्तव में याचिकाकर्ता ने आयातों के लैंडेड मूल्य से न्यूनतर कीमत पर अपनी बिक्री की है। समस्त क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतें स्थिर बनी रहीं और इसलिए कीमतों पर आयातों का प्रभाव सिद्ध नहीं होता है।
- 4) मांग स्थिर बनी रही जबकि विचाराधीन उत्पाद की स्वदेशी बिक्री में कोई गिरावट नहीं आई। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है। आयातों का हिस्सा भी स्थिर बना रहा। इसलिए घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
- 5) क्षमता उपयोग में कमी प्रतिवर्ष संयंत्र बंद होने के कारण आई। वास्तव में, जांच अवधि दौरान क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है।
- 6) वर्ष 2008-09 में घरेलू उद्योग के उत्पादन के हिस्से में गिरावट आई जबकि अन्य घरेलू विनिर्माताओं के उत्पादन में 12% की बढ़ोतरी हुई।
- 7) लाभदायकता में उस स्तर तक गिरावट नहीं आई जिस तक विचाराधीन उत्पाद का संबंध है, जबकि याचिकाकर्ता के अन्य खंडों पर प्रभाव पड़ा।
- 8) संबद्ध वस्तु के निर्यात में अत्यधिक कमी हुई है।
- 9) माल सूची में बढ़ोतरी संयंत्र बंद होने और निर्यात बिक्री में कमी होने के कारण।
- 10) संबद्ध वस्तु की बिक्री में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन में वृद्धि के अनुपाल से सुधार हुआ।
- 11) आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान उत्पादन में 30% की वृद्धि हुई। स्वदेशी बिक्री में भी 24% की वृद्धि दर्शाई गई है। पीबीआईटी में वृद्धि 30% है।
- 12) घरेलू उद्योग के दावे को न्यायोचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि क्षति अवधि के दौरान बेन्जीन की कीमतें स्थिर बनी रहीं जबकि घरेलू उद्योग के एनएसआर में सुधार आया।

अधिकांश क्षति अवधि में नकारात्मक कीमत कटौती हुई है। जांच अवधि में भी 5% का मार्जिनल अंतर पाया गया।

- 13) उत्पादन लागत और लगाई गई पूंजी पर आय की गणना करते समय प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के विगत तीन वर्षों के सर्वोत्तम निष्पादन पर विचार करना चाहिए।
- 14) घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में गिरावट आर्थिक मन्दी के कारण आई है और कंपनी की वार्षिक रिपोर्टों में इस स्थिति को स्वीकार किया गया है।
- 15) क्षमता उपयोग में गिरावट निर्यात मात्रा में गिरावट के कारण भी आई है।
- 16) यूके वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही की अवधि आर्थिक मन्दी से प्रभावित थी, इसलिए वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही से संबंधित बिक्रियों, आयातों और मांग का विश्लेषण पृथक रूप से किया जाना चाहिए।
- 17) संबद्ध वस्तु की लैंडिंग कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से हमेशा अधिक रही।
- 18) लाभ में कमी घरेलू उद्योग की लागत की तुलना में बिक्री कीमत में कमी के कारण आई है जबकि सीमा शुल्क में कटौती के बावजूद लैंडिंग कीमत एनएसआर से काफी अधिक है और इस प्रकार, लैंडिंग कीमत और घरेलू उद्योग की कीमत के बीच कोई संबंध नहीं है।
- 19) जांच की अवधि के दौरान कटौती अल्प थी परन्तु जांच की अवधि से पहले कटौती बहुत अधिक नकारात्मक थी जबकि वर्ष 2008-09 में घरेलू उद्योग का लाभ न्यून स्तर पर था। इसलिए, घरेलू उद्योग की लाभदायकता में क्षति अवधि के दौरान कीमत कटौती का कोई प्रभाव नहीं है।
- 20) न्यूनतर बिक्री प्रापण बेन्जीन की न्यून कीमतों के कारण है और इस प्रकार इसके लिए पाटित आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
- 21) संबद्ध वस्तुओं की अधिक मालसूची जीएनएफसी द्वारा जून, 2010 में क्रेताओं के साथ हस्ताक्षरित वार्षिक संविदा के कारण हुई जिसे अप्रैल 2010 में हस्ताक्षरित होना था। इससे वर्ष 2010-2011 की पहली तिमाही के दौरान बिक्री मात्रा प्रभावित हुई। मालसूची एवं बिक्री मात्रा का सत्यापन अवधि के पश्चात, के लिए भी किया जाना चाहिए।
- 22) उत्पादन लागत में बढ़ोतरी का दावा सही नहीं है क्योंकि बेन्जीन, जो एनिलिन की कुल लागत का लगभग 60-65% संघटक है, की कीमतें कम हुई हैं।

23) याचिकाकर्ता द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार शुरू किए जाने के साक्ष्य हैं। इसने भारत में संबद्ध वस्तु की बिक्री, सभी देशों से आयातित भारित औसत लैंडेड कीमत और अन्य घरेलू उत्पादकों की कीमत की तुलना में काफी न्यून कीमत पर बिक्री की।

24) संकेन्द्रित नाइट्रिक एसिड, जो एनिलिन के उत्पादन में प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, का उत्पादन याचिकाकर्ता करता है और तब इसे एनिलिन के उत्पादन के लिए अंतरित किया जाता है। याचिकाकर्ता ने उत्पादन लागत में वृद्धि का दावा किया है जबकि बेस वर्ष की तुलना में जॉच की अवधि में कच्चे माल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसलिए, यह संदेहपूर्ण है कि याचिकाकर्ता ने एनिलिन की लागत का निर्धारण करने के लिए कच्चे माल की अंतरण लागत या बाजार कीमत का प्रयोग किया है।

25) याचिकाकर्ता द्वारा एक ही संबद्ध वस्तु की दो पृथक जॉचों में प्रस्तुत आंकड़े बिक्री लागत और लाभ के रूप में अलग-अलग हैं परन्तु पीबीटी में परिवर्तन के बावजूद आरओआई समान हैं।

26) याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट में घरेलू उद्योग की क्षति के लिए कई अन्य तथ्यों को भी प्रकट किया गया है, जैसे अधोगामी उत्पाद का अल्प उठान, वैश्विक मन्दी एवं कटौती, बेन्जीन की न्यूनतर कीमतें, आर्थिक मन्दी, न्यूनतर प्रापण और वार्षिक बन्दी के कारण उच्च स्टॉक।

27) मात्रा क्षति विश्लेषण के संबंध में तथ्यों का मूल्यांकन करने के लिए समर्थक द्वारा दी गई मात्रा सूचना को ही ध्यान में रखा गया। यदि समर्थक के कीमत आंकड़ों पर भी विचार किया जाता तो 'आवेदक' और 'समर्थक' के बीच कोई भिन्नता नहीं रहती।

28) जॉच की अवधि के पश्चात घरेलू उद्योग के निष्पादन में तीव्र सुधार हुआ, जिससे यह संकेत मिलता है कि क्षति अवधि और जॉच की अवधि में कमी वैश्विक मन्दी के द्वारा निष्पादन में आई कमी के कारण हुई न कि कथित पाटन के कारण।

29) संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान क्षमता उपयोग 100% बना रहा, वर्ष 2008-09 के सिवाय जब प्लांट बंद होने और वैश्विक मन्दी के कारण काम में कमी आ गई।

30) जॉच अवधि के पश्चात के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि क्षति अस्थायी थी। जीएनएफसी की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख है कि वैश्विक मन्दी के पश्चात बाजार की स्थिति में सुधार होने के कारण बिक्री में वृद्धि हुई। उनकी वार्षिक रिपोर्ट की नई प्रत्याशाओं के आधार पर वर्ष 2010-11 में क्षमता उपयोग 114% है। बिक्री उत्पादन अनुपात 100% है।

- 31) कुल बिक्री में गिरावट के लिए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, परन्तु निर्यात बिक्री के लिए ये हो सकता है।
- 32) बाजार हिस्से का नुकसान पाटित आयातों से जुड़ा नहीं है परन्तु यह एचओसीएल के कारण हुआ जिसने न्यून क्षमता उपयोग बनाए रखा जिससे संबद्ध वस्तु का आयात करना पड़ा।
- 33) याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद की बिक्री व्यापारी के माध्यम से करता है और समर्थक इसकी उपभोक्ता को सीधी बिक्री करता है। अतः वो कीमत जिस पर याचिकाकर्ता मध्यवर्ती को बिक्री करता है, घरेलू उद्योग की कीमत के प्रतिनिधि के रूप में नहीं मानी जा सकती है क्योंकि ये वो कीमत नहीं है जिस पर उपभोक्ता विचाराधीन उत्पाद की खरीद करता है।
- 34) याचिकाकर्ता के लिए एनएसआर 60रु0/किग्रा. है परन्तु व्यापारी इसे बहुत अधिक उच्च कीमत पर बेचता है(गोपनीय)।
- 35) ट्रेडेक्स, मध्यवर्ती, अपनी बिक्रियों की कीमत का निर्धारण सुपुर्दग्गी के समय चल रही अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर करता है जबकि आयातक/उपभोक्ता बुकिंग की तारीख से लगभग दो महीने पश्चात वस्तु की डिलीवरी लेता है। इसलिए उस सीमा तक क्षति मार्जिन को तद्रुसार परिकलित करने की जरूरत है।
- 36) सभी प्रमुख पैरामीटरों में वृद्धि हुई है, जैसाकि प्रपत्र IVक में दर्शाया गया है।
- 37) अनुबंध III के अनुसार, लगाई गई पूंजी पर आय और उत्पादन लागत की गणना करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के सर्वोत्तम निष्पादन पर विचार करना चाहिए। और इसलिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी को तद्रुसार पीओसीई का निर्धारण करना चाहिए।
- 38) सीएनए, एनिलिन के लिए नाजुक कच्चा माल है, का उपभोग कैप्टिवली किया जाता है। आवेदक ने स्वीकार किया है कि इसे सह-उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए, इसकी कीमत को न्यूनतर आधार पर लिया जाना चाहिए न कि बाजार कीमत आधार पर, जैसाकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्ताव किया गया है। यदि बाजार कीमत के आधार पर सीएनए की अंतरित कीमत को स्वीकार किया जाए तो सीएनए के संबंध में लगाई गई पूंजी एनिलिन के लिए लगाई गई पूंजी में नहीं जोड़ी जानी चाहिए।
- 39) निर्दिष्ट प्राधिकारी को आवेदक द्वारा रखी गई रिकॉर्ड पुस्तिकाओं की जाँच करनी चाहिए और कैप्टिव उपभोग कीमतों, न कि बाजार मूल्य को, गिना जाना चाहिए।
- 40) वर्तमान मामले में केवल एकल विनिर्माता अर्थात् जीएनएफसी के लिए परिष्कृत उत्पाद की कुल लागत की गणना करते समय मध्यवर्ती अर्थात् सीएनए की बाजार कीमत या

विनिर्माण लागत (इनमें से जो भी कम हो), पर विचार किया जाना चाहिए और यदि बाजार कीमत पर विचार किया जाता है तो उस मध्यवर्ती के लिए लगाई गई पूंजी परिष्कृत उत्पाद पर लगाई गई कुल पूंजी का एक भाग नहीं होना चाहिए।

- 41) कोई कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं होता है क्योंकि क्षति संयंत्र बंद होने, वैशिक मंदी और बेन्जीन की कीमतें कम होने के कारण हुई।
- 42) याचिकाकर्ता मांग पूरी नहीं कर सका और याचिकाकर्ता के निष्पादन में जांच अवधि के पश्चात बहुत सुधार हुआ है।
- 43) एचओसीएल द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को पूरी तरह से नकार देना चाहिए क्योंकि वे समय सीमा और जांच की भागीदारी के संबंध में संगत अनुजप्ति की अपेक्षा को पूरा करने में असफल रहे। एचओसीएल आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि उनके द्वारा सहन की गई क्षति, यदि कोई, पूरी तरह से उनके आंतरिक कारण से हुई और अन्य कारणों से हुई क्षति के लिए पाटन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- 44) याचिकाकर्ता ने एक माह के सर्वोत्तम उत्पादन के आधार पर प्राप्त करने योग्य क्षमता का दावा किया है, जो गलत है। याचिकाकर्ता को क्षति का निर्धारण संपूर्ण वर्ष की क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए जो वार्षिक रिपोर्ट पर आधारित होनी चाहिए।
- 45) क्षति विश्लेषण में घरेलू एवं निर्यात प्रचालनों के लिए क्षमता एवं उत्पादन मात्रा को अलग-अलग नहीं किया जा सकता है।
- 46) जांच की अवधि को छोड़कर संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की बिक्री कीमत लैंडेड कीमत तथा अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री कीमतों से अत्यधिक कम थी। वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 में बिक्री कीमत में कमी विदेशी उत्पादकों द्वारा पाटन के कारण नहीं हुई। इसलिए पाटन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। घरेलू उद्योग द्वारा लैंडेड कीमत से न्यून कीमत पर बिक्री करने का कोई कारण नहीं दिया गया है, जबकि संबद्ध देश से कथित पाटन नहीं हुआ था।
- 47) याचिकाकर्ता ने कच्चे माल पर जानकारी देने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया है। संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत में वृद्धि कच्चे माल की कीमतों में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक थी।
- 48) चूंकि जांच की अवधि के पहले 6 महीने आर्थिक मन्दी से प्रभावित रहे, इसलिए पीओआई पश्चात् आंकड़े असंगत हो जाते हैं।
- 49) याचिकाकर्ता की बिक्री कीमत अन्य घरेलू उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों की बिक्री कीमत अन्य देशों के बारे में प्रभावी मौजूदा एडीडी के बावजूद निरंतर कम रही हैं। इस न्यून बिक्री के कारण की विस्तार से जांच की जानी चाहिए।

50) पूर्वापेक्षी प्रभाव से शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि धारा 9क(3) की पूर्वापेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया। संबद्ध देश के बारे में पाटन का कोई इतिहास नहीं है। इसे सिद्ध करने की जिम्मेदारी घरेलू उद्योग की है। याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन साक्ष्यों पर आधारित नहीं हैं। यह उच्चतर सामान्य मूल्य और अवास्तविक समायोजन के कारण न्यूनतर निर्यात कीमत के कारण अत्यधिक बढ़ा हुआ है। इसलिए, भारी पाटन का मामला ही नहीं बनता है।

51) याचिकाकर्ता ने, याचिका के विरुद्ध लिखित प्रस्तुतीकरण में घरेलू उद्योग के विस्तार में संशोधन किया है।

52) याचिकाकर्ता द्वारा एचओसीएल की ओर से किए गए दावे के आधार पर क्षति की जाँच में क्षति सूचना/आंकड़ों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस अपवादस्वरूप स्थिति का सही उपचार वर्तमान जाँच में अपृथक्करणीय है क्योंकि उसका घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति सिद्ध करने में काफी प्रभाव है, जैसाकि ईसी ने धारित किया है।

53) जाँच की अवधि में याचिकाकर्ता(जीएनवीएफवी) का क्षमता उपयोग 101% के स्तर पर बना रहा जबकि एचओसीएल का क्षमता उपयोग संपूर्ण क्षति अवधि में 21% से 28% के स्तर पर था।

54) यदि जीएनवीएफसी और एचओसीएल दोनों ही प्रतिस्पर्धी हैं और केवल पाटन की वजह से समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो उनकी लागत और परिणामस्वरूप उससे लाभ में इतना बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। एचओसीएल का भारी घाटा आयातों के अतिरिक्त अन्य तथ्यों के कारण हुआ न कि पाटन के कारण।

55) एचओसीएल द्वारा सहन की गई क्षति और कथित पाटित आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। केवल जीएनवीएफसी के आंकड़े ही यह दर्शाते हैं कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का निष्पादन मॉडरेट रहा और यह जाँच की अवधि के पश्चात अर्थात 2010-11 में आसमान छूने लगा। एचओसीएल के आंकड़ों को शामिल करने से सारी तस्वीर बदल जाएगी क्योंकि उनको हुई क्षति कुछ आंतरिक कारणों से हुई है।

56) चूंकि संकेन्द्रित नाइट्रिक एसिड का उत्पादन याचिकाकर्ता द्वारा अपनी कंपनी में किया जाता है, इसलिए संकेन्द्रित नाइट्रिक एसिड की दर को लागत के रूप में विचारा जाना चाहिए। आईसीआईएस एलओआर रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर बनाई जाती हैं, इसलिए प्राधिकारी को चाहिए कि वह बेन्जीन की दर को साप्ताहिक रिपोर्ट से आंका जाना चाहिए और इसकी वित्तीय लागत पर विधार याचिकाकर्ता की वास्तविक लागत, न कि

आकलन, के आधार पर किया जाना चाहिए।

57) वास्तविक प्राप्त करने योग्य क्षमता की कोई संकल्पना नहीं है, जैसाकि याचिकाकर्ता ने की है और इसलिए इस तर्क में विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।

58) यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता के निर्यातों में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान पर्याप्त गिरावट आई जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के प्रचालनों पर प्रभाव पड़ा, परन्तु इससे घरेलू प्रचालनों पर, जो क्षति की विषय वस्तु हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस मुद्दे का विस्तार से विश्लेषण करने की जरूरत है।

59) जाँच अवधि के पश्चात, के आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए जैसाकि एनएफवाई के मामले में किया गया है।

60) जाँच की अवधि में बेन्जीन की लागत में भी कमी आई है। तब घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में बढ़ोत्तरी का दावा कैसे कर सकता है।

61) घरेलू उद्योग ने एक ही आरओआई से विभिन्न लागत बिक्री और लाभ का दावा किया है। हालांकि दो पृथक जाँचों में पीबीआईटी में परिवर्तन हुआ है।

62) चूंकि आयातों की लैंडेड कीमत का परिकलन बीजक तारीख में किए गए उल्लेख के आधार पर किया जाता है, इसलिए घरेलू बिक्री कीमत की लैंडेड मूल्य से तुलना भी बीजक तारीख से जुड़ी होनी चाहिए न कि पोतलदान की तारीख से। पोलीप्रोपिलीन के मामले में इसी सिद्धान्त का पालन किया गया है।

63) प्रपत्र IV ख संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं दर्शाता है। आधार वर्ष के दौरान नकारात्मक कीमत कटौती भी यही सुनिश्चित करती है।

64) याचिकाकर्ता की वर्षिक रिपोर्ट इसके विपरीत सूचना प्रदान करती है क्योंकि वहां इस निष्पादन में सुधार हुआ है।

65) घरेलू उद्योग द्वारा दावाकृत क्षति न्यायोचित नहीं है। यह याचिका एनआईपी और कटौती जैसे भौतिक तथ्यों के संबंध में शांत है।

66) घरेलू उद्योग की बिक्रियाँ एक मध्यवर्ती व्यापारी के जरिए की गई हैं। इसलिए इसकी कीमत को घरेलू उद्योग की कीमत के रूप में नहीं विचारा जाना चाहिए। इसकी न्यून कीमत के कारण हुई क्षति, इसकी मध्यवर्तियों को की गई बिक्री के कारण हुई है न कि आयातों के कारण। यह एक स्वयंसिद्ध क्षति है।

67) एनआईपी और कम बिक्री की मात्रा का अन्य पक्षकारों को खुलासा नहीं किया गया है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच

33. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। इस संबंध में विभिन्न प्राचलनों की जांच से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विरोधी पक्षकारों ने केवल एक उत्पादक से जानकारी प्राप्त होने पर विचार करते हुए किसी भी क्षति के न होने का तर्क दिया है। तथापि, कोई भी पक्षकार कोई विधिक आधार बताने में सक्षम नहीं रहा है कि क्षति के लिए केवल एक उत्पादक के आंकड़ों पर विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उपभोक्ताओं ने ग्वाटेमाला से मैक्सिको स्टील पाइप्स और ट्यूब्स पर पाटनरोधी शुल्क से संबंधित मामले में डब्ल्यूटीओ निर्णय का उल्लेख किया है। उक्त निर्णय में यह स्पष्ट होता है कि कोई जांचकर्ता प्राधिकारी जांच शुरू करने के लिए आंशिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसे बाद में जाँच प्रक्रिया के दौरान दिया जा सकता है और क्षति की जाँच परिभाषित घरेलू उद्योग के लिए, न कि परिभाषित घरेलू उद्योग के बड़े भाग के लिए, की जानी चाहिए। इस मामले में जांच शुरूआत अधिसूचना में यथाउलिलिखित जांच की शुरूआत के समय एचओसीएल ने याचिका का समर्थन किया था और तदुपरान्त कंपनी ने लागत निर्धारण संबंधी संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत कर दी जिसका प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है। इसलिए, प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों के तर्क में कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

34. जांच की अवधि के पश्चात के निष्पादन के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के पश्चात सभी अन्य पैरामीटरों में परिवर्तन हो सकता है जिनकी संपूर्ण जांच के जरिए ही जांच एवं परीक्षण किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों को नियम 23 के अन्तर्गत समीक्षा के लिए आवेदन करने का अधिकार है। वर्तमान जांच में जांच की अवधि के पश्चात के निष्पादन से कोई संगतता नहीं है।

35. कुछ हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि सीएनए एक उप-उत्पाद है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जीएनएफ द्वारा सीएनए का उत्पादन उप-उत्पाद के रूप में नहीं किया जाता है जबकि व्यर्थ जा रही गैस से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। इस दावे के संबंध में कि याचिकाकर्ता मांग पूरी नहीं कर सकता, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह एक पूर्वापेक्षा नहीं है कि याचिकाकर्ता भारत में उत्पाद की मांग पूरी करे। घरेलू उद्योग द्वारा व्यापारी के जरिए बिक्री

के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि व्यापार के समान स्तर पर तुलना की गई है।

36. एनएफवाई जांच में विचार किए गए जांच अवधि के पश्चात के आंकड़ों के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह उल्लेख अनुचित है क्योंकि उक्त जांच सनसेट समीक्षा जांच थी जिसमें प्राधिकारी ने क्षति की संभावना का परीक्षण किया था।

37. घरेलू उधोग द्वारा 100% संयंत्र उपयोग के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उधोग समय रूप से इसकी 100% क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा है। घरेलू उधोग के एक संघटक द्वारा 100% संयंत्र उपयोग के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दावा विधि द्वारा समर्थित नहीं है। नियमों में बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग आदि में वास्तविक और संभावित गिरावट का प्रावधान किया गया है। तथ्य यह है कि घरेलू उधोग के उक्त संघटक द्वारा उत्पादन में गिरावट का सामना किया गया।

38. निर्यातों में गिरावट के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उधोग के निर्यातों में गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उधोग ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण घरेलू बाजार में हुई क्षति और घरेलू निष्पादन संबंधी क्षति के बारे में अलग-अलग जानकारी दी है। इस प्रकार, दावा की जा रही क्षति केवल घरेलू बाजार में निष्पादन के कारण आई क्षति है। इसके अतिरिक्त, निर्यातों में गिरावट की तुलना में आयातों में वृद्धि बहुत अधिक हुई है।

39. नकारात्मक कीमत कटौती के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कीमत कटौती केवल जांच की अवधि के लिए ही संगत है। नकारात्मक कीमत कटौती यह दर्शाती है कि विगत में कोई क्षति नहीं हुई क्योंकि कटौती नकारात्मक थी जबकि जांच की अवधि में सकारात्मक कटौती यह दर्शाती है कि लैंडेड कीमत घरेलू उधोग को अपने कीमतें कम करने के लिए विवश करती रही है।

40. पाटनरोधी नियमों के नियम 11 के साथ पठित अनुलग्नक-II में यह प्रावधान है कि क्षति का निर्धारण करने में उन सभी तथ्यों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उधोग को क्षति का संकेत मिलता हो, इसमें पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान मद के लिए कीमतों पर उनका प्रभाव और संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार किया जाएगा। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक विचारा गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत कटौती की जा रही है।

अथवा इन आयातों का प्रभाव काफी हद तक कीमतों को अन्यथा कम करने या उन्हें काफी हद तक बढ़ने, जोकि घटित हुआ होता, से रोक रही हैं।

41. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के साथ पठित पैरा (iv) में उल्लेख है कि:

“घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक या संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों, घरेलू उद्योग की कीमत को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजीनिवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का तद्देश्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।”

42. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा और पाटन का मार्जिन ऊपर निर्धारित सीमा से अधिक है। भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उद्योग की स्थिति के संबंध में अन्य मानदंडों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री प्रमात्रा, स्टॉक, लाभदायकता, निवल बिक्री प्रापण, पाटन मार्जिन और उसकी मात्रा आदि पर सुपरा नियमों के अनुबंध II (iv) के अनुसार विचार किया है।

45. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में प्रावधान है कि (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव और (ख) इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव, दोनों की उद्देश्यपरक जाँच की जाए। पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव की जांच करते समय प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समग्र रूप से या उत्पादन अथवा खपत के संबंध में पाटित आयातों में वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी से यह जांच करने की अपेक्षा की जाती है कि भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा कीमत में कटौती हुई है अथवा इन आयातों का प्रभाव कीमत को काफी हद तक कम करेगा या उसे बढ़ने से रोकेगा जो अन्यथा बढ़ गई होती।

46. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के पैरा (iv) में उल्लेख है कि, “घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक या संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों, घरेलू उद्योग की कीमत को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूँजीनिवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित क्रृत्यात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।”

47. याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है। याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग हैं। अतः प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को घरेलू उद्योग के रूप में माना है।

48. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति पैरामीटरों की उद्देश्यपरक जांच की है।

च.4 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

49. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में यह जांच की गई कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के संगत रूप से अत्यधिक वृद्धि हुई है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II(ii) में निम्नलिखित प्रावधान है:

“पाटित आयातों की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी विचार करंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के संगत रूप से अत्यधिक वृद्धि हुई है।”

च.5 आयात की मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा

50. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा निम्नानुसार रही है:

	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि - 15 माह	जांच अवधि वार्षिकीकृत
संबद्ध देश/भूभाग-ईयू	7,006	1,821	8,874	23,394	18,715
शुल्क आकृष्ट करने वाले	6,108	6,074	-	1,497	1,198

देश					
अन्य - देश	17	10,799	-	23	18
कुल	13,131	18,694	8,874	24,914	19,931
बाजार हिस्सा					
संबद्ध देश/भूभाग-ईयू	53.36%	9.74%	100.00%	93.90%	93.90%
शुल्क आकृष्ट करने वाले देश	46.52%	32.49%	0.00%	6.01%	6.01%
अन्य - देश	0.13%	57.77%	0.00%	0.09%	0.09%
भारतीय उत्पादन	47,377	47,981	39,100	56,775	45,420
भारतीय उत्पादन की तुलना में ईयू से आयात	15%	4%	26%	46%	46%
भारत में मांग	58,393	65,082	47,636	78,246	62,597
संबद्ध देश से मांग के संबंध में आयात	12%	3%	19%	30%	30%

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का संबद्ध देश से आयात में समग्र रूप से और देश में उत्पादन और खपत के संबंध में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- ख. अन्य देशों से आयात में कमी आई और वे जांच की अवधि में लगभग पूरी तरह से बंद हो गए हैं।
- ग. संबद्ध देश से आयातों का बाजार हिस्सा संपूर्ण क्षति अवधि, 2008-09 को छोड़कर, बढ़ा है और भारत में इसकी मांग 30% के स्तर तक पहुंच गई है।

च.6 मांग और बाजार हिस्से का आकलन

52. संबद्ध वस्तु की मांग का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी देशों से आयातों को जोड़कर किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते

हैं कि संबद्ध वस्तु के लिए मांग में आधारभूत वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि - 15 माह	जांच अवधि वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग	45,262	43,388	33,562	47,333	37,866
अन्य भारतीय उत्पादक	0	3000	5200	6000	4800
संबद्ध देश	7,006	1,821	8,874	23,394	18,715
अन्य देश - शुल्क आकृष्ट करने वाले	6,108	6,074	-	1,497	1,198
अन्य देश	17	10,799	-	23	18
मांग	58,393	65,082	47,636	78,246	62,597
बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	78%	67%	70%	60%	60%
अन्य भारतीय उत्पादक	0%	5%	11%	8%	8%
संबद्ध देश	12%	3%	19%	30%	30%
अन्य देश - शुल्क आकृष्ट करने वाले	10%	9%	0%	2%	2%
अन्य देश	0.03%	16.59%	0.00%	0.03%	0.03%

53. उपर्युक्त तालिका से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि

- क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में समग्र रूप से, 2008-09 को छोड़कर, वृद्धि हुई है। वर्ष 2008-09 के बाद जांच की अवधि में मांग में पुनः वृद्धि हुई।
- ख. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में अत्यधिक कमी आई।

ग. संबद्ध देश का बाजार हिस्सा बहुत अधिक बढ़ गया और जांच की अवधि में यह दोगुने से ज्यादा हो गया।

घ. अन्य देशों का बाजार हिस्सा जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा था, बहुत अधिक कम हो गया।

54. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ईयू से आयात कीमतों में अत्यधिक कमी आई है, जैसाकि अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है जिससे यूरोपियन यूनियन से आयातों में बढ़ोतरी हुई और ईयू ने अधिकांश बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया।

	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि - 15 माह
यूरोपियन यूनियन से मी.टन में आयात	7,006	1,821	8,874	23,394
आयातों का मूल्य लाख रु०	4,148.26	1,078.61	5,733.37	12,532.66
औसत कीमत रु०/मी.टन	59,210	59,234	64,612	53,573
औसत कीमत रु०/मी.टन - सूचीबद्ध	100	100	109	90

च.7. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और कीमत को प्रभावित करने वाले अन्य तथ्य

55. नियम 18 के उप नियम (2) में यथाउलिखित पाटित आयातों का कीमतों पर प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादन की कीमत की तुलना में कीमतों में बहुत अधिक कमी हुई है या इन आयातों का प्रभाव पर्याप्त हद तक कीमतों को अन्यथा प्रभावित करता है या कीमतों में वृद्धि होने से रोकता है जो आयात न होने की स्थिति में पर्याप्त रूप से हुई होती।

56. संबद्ध वस्तु से पाटित आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत के कारण कम बिक्री, कीमत पतन और कीमत हास के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य के लिए घरेलू उद्योग की भारित औसत उत्पादन लागत,

निवल बिक्री प्राप्ति और गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

च.8 कीमत कटौती और कम बिक्री

57. कीमत कटौती का निर्धारण संपूर्ण जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से पाटित आयातों के लैंडेड मूल्य की उसी अवधि के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ तुलना करके किया गया। इस उद्देश्य के लिए आयातों के लैंडेड मूल्य का परिकलन 1% हैंडलिंग प्रभार और लागू आधारभूत सीमाशुल्क तथा संबद्ध देश से आयात कीमतों के आईबीआईएस आंकड़ों में सूचित उप-कर की कीमत को जोड़कर किया गया।

58. कीमत के कारण कम बिक्री के उद्देश्य के लिए संबद्ध देश से आयातों के लैंडेड मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की जांच अवधि के दौरान निर्धारित गैर-क्षतिकारी कीमत से की गई है।

विवरण	यूनिट	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि
निवल बिक्री प्राप्ति	रु0/किग्रा.	***	***	***	***
आयात की लैंडेड कीमत	रु0/किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु0/किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	(0-10)	(0-10)	(5-15)	0-10
गैर क्षतिकारी कीमत	रु0/किग्रा.	***	***	***	***
कीमत के कारण कम बिक्री	रु0/किग्रा.				***
कीमत के कारण कम बिक्री	%				***
कीमत के कारण कम बिक्री	% रेंज				5-15

59. उपर्युक्त तालिका से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु का संबद्ध देश से पाटित आयातों के लैंडेड मूल्य के कारण जांच अवधि के दौरान घरेलू कीमत में अत्यधिक कटौती हुई। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देश से लैंडेड मूल्य घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत से काफी कम था।

च.9 पाटित आयातों का कीमत निग्रहण और हास प्रभाव

60. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों का निग्रहण या हास हो रहा है, प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया कि क्या इन आयातों के प्रभाव से कीमतों में बहुत अधिक कमी हुई है या इन आयातों का प्रभाव पर्याप्त हद तक कीमतों को अन्यथा प्रभावित करता है या कीमतों में वृद्धि होने से रोकता है जो आयात न होने की स्थिति में पर्याप्त रूप से हुई होती। इस उद्देश्य के लिए संबद्ध वस्तु की आयात कीमतों की तुलना घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत की प्रवृत्ति से की गई।

		2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि -15 माह
बिक्री लागत	रु0/मी.टन	***	***	***	***
सूची	प्रवृत्ति	100	99	111	106
बिक्री कीमत	रु0/मी.टन	***	***	***	***
सूची	प्रवृत्ति	100	93	99	95
लाभ/हानि	रु0/मी.टन	***	***	***	***
सूची	प्रवृत्ति	100	(206)	(543)	(530)

61. प्राधिकारी निम्नवत् नोट करते हैं:

- घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यद्यपि, पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है फिर भी जांच की अवधि की उत्पादन लागत आधारभूत वर्ष की उत्पादन लागत की तुलना में अधिक है।

- ii. उत्पादन लागत में वृद्धि के बावजूद आधारभूत वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कमी आई है।
- iii. संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत में उत्तर-चढ़ाव यह दर्शाता है कि जांच अवधि के दौरान उत्पादन लागत में 6% की वृद्धि हुई जबकि इसके विपरीत बिक्री कीमत में क्षति अवधि की तुलना में 5% कमी आई।
- iv. घरेलू उद्योग ने आधारभूत वर्ष में मुनाफा कमाया था परन्तु जांच अवधि में घाटे में बढ़ोतरी हुई।

62. उपर्युक्त विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के बावजूद घरेलू उद्योग ने इसकी बिक्री कीमत में कटौती की। अतः यह प्रतीत होता है कि पाटित आयातों की न्यून कीमत में घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य किया।

च.10 अन्य क्षति पैरामीटरों की जांच

63. उपर्युक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप से और बाजार हिस्से में वृद्धि के अनुरूप मात्रा एवं कीमत के रूप में विपरीत प्रभाव पड़ा है। संबद्ध वस्तु के बारे में कीमत कटौती सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण रही। बिक्री कीमत में उत्तर-चढ़ाव उत्पादन लागत में उत्तर-चढ़ाव के अनुरूप नहीं रहा। घरेलू उद्योग को मात्रा एवं कीमत क्षति दोनों तरह से नुकसान हुआ है।

64. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में इन आयातों का ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों को परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच शामिल होगी। इन आयातों का इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करते समय समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक या संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों, घरेलू उद्योग की कीमत को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजीनिवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित कृष्णात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग से संबंधित

विभिन्न क्षति प्राचलों का वर्णन निम्नलिखित है:

क. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

65. घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग निम्नानुसार है:

	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि - 15 माह	जांच अवधि वार्षिकीकृत
क्षमता मी.टन	60,100	60,100	60,100	75,125	60,100
उत्पादन मी.टन	47,377	44,981	33,900	50,775	40,620
बिक्री मी.टन	45,262	43,388	33,562	47,333	37,866
क्षमता उपयोग %	79%	75%	56%	68%	68%

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि-

क. घरेलू उद्योग की क्षमता वर्षों तक वही बनी रही।

ख. देश में पर्याप्त मांग के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री में, यूरोपियन यूनियन से पाइत आयतों की उपलब्धता के कारण, कभी आई जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट हुई। हालांकि वर्ष 2008-09 की तुलना में जांच अवधि में उत्पादन में वृद्धि हुई, फिर भी यह पिछले स्तर से कम बनी रही।

ख. लाभ, निवेश पर आय एवं नकदी प्रवाह

67. निम्नलिखित तालिका से घरेलू उद्योग के लाभ, पूँजी पर आय और नकद प्रवाह की जानकारी मिलती है:

		2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि -15 माह
उत्पादन लागत	रु0/मी.टन	***	***	***	***
सूची	प्रवृत्ति	100	99	111	106

बिक्री कीमत	रु0/मी.टन	***	***	***	***
सूची	प्रवृत्ति	100	93	99	95
ब्याज एवं कर पूर्व लाभ	रु0/मी.टन	***	***	***	***
सूची	प्रवृत्ति	100	(206)	(543)	(530)
नकद लाभ	रु0/लाख	***	***	***	***
सूची	प्रवृत्ति	100	(50)	(137)	(198)
निवेश से आय	%	***	***	***	***
सूची	सूची	100	(167)	(367)	(533)
लगाई गई पूंजी	रु0 लाख	***	***	***	***

68. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- i. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान इसमें कमी आई फिर भी जांच अवधि में उत्पादन लागत आधारभूत वर्ष की तुलना में अधिक है।
- ii. उत्पादन लागत में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई।
- iii. संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत में उत्तार-चढ़ाव यह दर्शता है कि जांच अवधि के दौरान उत्पादन लागत में 6% की वृद्धि हुई जबकि बिक्री कीमत में 5% की गिरावट आई।
- iv. हालांकि घरेलू उद्योग ने आधारभूत वर्ष में लाभ कमाया, परन्तु वर्ष 2007-08 में इसको नुकसान हुआ।
- v. उत्पादन लागत में वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं कर सका जिसके कारण नुकसान हुआ।
- vi. निवेश पर आय और नकद लाभ में भी गिरावट आई और वे वर्ष 2007-08 से नकारात्मक हो गए।
- vii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जीएनएफसी को कोई क्षति नहीं हुई और एचओसीएल को क्षति अन्य कारकों से हुई। प्राधिकारी ने जीएनएफसी के आंकड़ों का अलग से परीक्षण किया और यह नोट किया कि जीएनएफसी के निष्पादन पर पाटित आयातों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, साथ ही जीएनएफसी द्वारा लगाई गई पूंजी पर आय में भी पर्याप्त गिरावट आई।

ग. उत्पादकता

69. निम्नलिखित तालिका से घरेलू उद्योग की उत्पादकता संबंधी जानकारी मिलती है:-

		2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि वार्षिकीकृत
उत्पादकता प्रति दिन	मी.टन प्रति दिन	***	***	***	***
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन प्रति सं.	***	***	***	***
सूची		100	93	72	86

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की प्रति दिन आधार पर और प्रति कर्मचारी उत्पादता में कमी आई है। यद्यपि, वर्ष 2008-09 की तुलना में जांच की अवधि में उत्पादकता में वृद्धि हुई है परन्तु यह आधार वर्ष के स्तर से कम बनी रही।

घ. रोजगार एवं मजदूरी

71. घरेलू उद्योग के रोजगार एवं मजदूरी के संबंध में सूचना निम्नलिखित सारणी में उपलब्ध कराई गई है:

		2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि 15 माह	जांच अवधि वार्षिकीकृत
रोजगार	सं0	***	***	***	***	***
सूची		100	102	99	99	99
मजदूरी	रु0 लाख	***	***	***	***	***
सूची		100	97	109		130

72. यह नोट किया जाता है रोजगार में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया क्योंकि घरेलू उद्योग में कई बहु-उत्पाद कंपनियां शामिल हैं। तथापि, जांच की अवधि के दौरान मजदूरी में वृद्धि हुई है।

उ. माल सूची

73. नीचे दी गई सारणी घरेलू उद्योग के साथ मालसूची के स्तर को दर्शाती है:

		2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि - 15 माह
मालसूची	मी.टन	***	***	***	***
सूची		100	153	156	705
बिक्री दिनों के लिए मालसूची	दिनों की संख्या	***	***	***	***
सूची		100	166	224	905

74. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की माल-सूची में विगत वर्ष की तुलना जांच की अवधि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। बिक्री मात्रा में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग की मालसूची में बढ़ोतरी हुई है। प्राधिकारी ने बिक्री के दिनों की संख्या के लिए मालसूची की जांच की और यह नोट किया कि मालसूची जो आधार वर्ष में केवल 4 दिन कम थी, जांच की अवधि में बढ़कर एक माह से अधिक हो गई।

च. पाटन की मात्रा

75. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटन की मात्रा इस बात की सूचक है कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को किस हद तक क्षति हो सकती है और वर्तमान मामले में यह दर्शाती है कि जांच अवधि के लिए संबद्ध देश के विरुद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन बहुत अधिक है।

छ. वृद्धि

76. अधिकांश पैरामीटरों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, मालसूची, बाजार हिस्सा, लाभ, निवेश पर आय, नकद लाभ और उत्पादकता के रूप में घरेलू उद्योग की वृद्धि

नकारात्मक है। आधार वर्ष की तुलना में उत्पादन में 14% की गिरावट आई, आधार वर्ष की अपेक्षा बिक्री में 16% की कमी आई, सम्बद्ध देश से आयातों में आधार वर्ष की तुलना में 165% की बढ़ोत्तरी हुई, आधार वर्ष की अपेक्षा लाभदायकता में 63% की कमी आई, नकद लाभ में 298% की कमी आई, निवेश पर आय में गिरावट आकर सकारात्मक से नकारात्मक हो गया।

छ. क्षति सम्बन्धी निष्कर्ष

77. क्षति के सम्बन्ध में प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

- i. विचाराधीन उत्पाद के सम्बद्ध देश से आयातों में समग्र रूप में तथा भारत में उत्पादन एवं खपत के रूप में आयातों में वृद्धि हुई।
- ii. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी हद तक कटौती हो रही है।
- iii. आयात, घरेलू उद्योग की कीमत का हास कर रहे हैं और कीमतों में बढ़ोत्तरी, जो पाठन के प्रभाव के कारण होती है, होने से रोक रहे हैं।
- iv. घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, माल सूची, बाजार हिस्सा, लाभ, आय पर निवेश, नकद लाभ, उत्पादकता आदि के रूप में पतन हुआ है।
- v. रोजगार और मजदूरी की प्रवृत्ति पर विचार करना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि याचिकाकर्ता एक बहु-उत्पाद कम्पनी है और रोजगार एवं मजदूरी पूरी तरह से सम्बद्ध वस्तु के निष्पादन पर निर्भर नहीं है।

78. प्राधिकारी, एतद्वारा, यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सम्बद्ध वस्तु का सम्बद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है।

ज. कारणात्मक संबंध

79. निम्नलिखित कारणात्मक संबंध स्थापित होता है:

- i. सम्बद्ध देश से एनिलिन के आयात में समग्र रूप में वृद्धि हुई है।
- ii. यूरोपियन यूनियन से भारत को हुए कुल आयातों की तुलना में अन्य देशों से हुए आयातों का कोई महत्व नहीं है। इसके अतिरिक्त, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों पर पाठनरोधी शुल्क पहले से ही लगा है और सनसेट

समीक्षा जाँच चल रही है। अतः, अन्य देशों से आयात, घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचा रहे हैं।

- iii. सम्बद्ध वस्तु की मांग में कोई संकुचन नहीं आया है। वास्तव में, मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग में पर्याप्त क्षमता है। तथापि, पाटन के कारण, घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की बिक्री करने में सक्षम नहीं थे और, इस कारण उत्पादन में कमी आई तथा मालसूची में वृद्धि हुई।
- iv. यह सिद्ध करने के लिए कि सम्बद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यूरोपियन यूनियन से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि ने घरेलू उद्योग को, घरेलू मांग में वृद्धि के बावजूद अपनी बिक्री और बाजार हिस्सा बढ़ाने में अवरोध उत्पन्न किया। बिक्री में गिरावट से उत्पादन में गिरावट आई और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में कमी हुई। घरेलू उद्योग एनिलिन का विनिर्माण करने के लिए अपेक्षित कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण आयातित उत्पाद की लैण्डिंग कीमत का मुकाबला करने में असफल रहा। सम्बद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों को कम करना पड़ा जिससे घरेलू उद्योग अपने कीमत स्तर को तर्कसंगत स्तर से न्यून बनाने के लिए विवश हो गया। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ। अतः घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति उक्त देश से प्राप्त आयातों के कारण हुई।

झ. अन्य जात तथ्यों की जांच

प्रौद्योगिकी का विकास

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई तर्क नहीं उठाया है। अतः, यह नोट किया जाता है कि सम्बद्ध वस्तु का उत्पादन करने की तकनीक और उत्पादन प्रक्रिया स्थिर हैं और इस कारण से घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं हुई है।

निर्यात निष्पादन

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निर्यात में गिरावट आई। तथापि, घरेलू उद्योग ने सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के पाटन के कारण घरेलू बाजार में इसको हुई क्षति की पृथक जानकारी दी है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा दावा की जा रही क्षति केवल घरेलू बाजार में

निष्पादन के कारण हुई क्षति है।

82. कोई अन्य तथ्य, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना हो, को प्राधिकारी के संजान में नहीं लाया गया।

कारण-कार्य संबंध निष्कर्ष

83. पाटित आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आई। पुनः यह देखा जा सकता है कि सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आई जिसके परिणामस्वरूप मांग में वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री कम हो गयी। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के उत्पादन और परिणामी क्षमता उपयोग में कमी हुई।

84. इसके अतिरिक्त, पाटित आयातों से कीमतें कम होने के कारण घरेलू उद्योग इसकी उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप कीमतें बढ़ाने में असफल रहा। परिणामस्वरूप जाँच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर आय में गिरावट आई।

85. अतः, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सम्बद्ध देश में उत्पादित या वहाँ से निर्यातित पाटित आयातों के कारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 के आशय के अन्तर्गत घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई।

क्षति मार्जिन का अर्थ

86. क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा, निर्धारित की जाने वाली प्रस्तावित गैर क्षतिकारी कीमत की तुलना निर्यातों की पहुँच कीमत से की गई। सम्बद्ध देश से निर्यातों की भारित औसत लैण्डिङ कीमत और क्षति मार्जिन का निर्धारण निम्नलिखित रूप से किया गया।

क्षति मार्जिन का परिकलन

87. प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बिक्री के लिए सम्बद्ध वस्तु के उत्पादन की गैर क्षतिकारी कीमत और सम्बद्ध वस्तु की सम्बद्ध देश से आयात की लैण्डिङ कीमत पर विचार करते हुए किया। गैर क्षतिकारी कीमता का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के अनुसार किया गया है। सभी कैप्टिव इनपुटों पर उनकी लागत पर

विचार किया गया और कैप्टिव इनपुट से सम्बंधित औसत निवल अचल परिसम्पत्तियों पर 22% की दर से अतिरिक्त आय का प्रावधान किया गया। हितबद्ध पक्षकार द्वारा लगाए गए इस आरोप के संबंध में कि एचओसीएल की उत्पादन लागत अन्य कारणों की वजह से अधिक है, प्राधिकारी ने एचओसीएल के उत्पादन की लागत के संबंध में इसके प्लांट में सम्बद्ध वस्तु के 100% क्षमता उपयोग और अन्य तथ्यों के कारण हुई क्षति, यदि कोई, को अलग करते हुए कैप्टिव मध्यवर्तियों पर विचार किया। निर्धारित की गई गैर क्षतिकारी कीमत और क्षति मार्जिन निम्नलिखित हैं:-

एनआईपी	(रु./किग्रा.)	***
लैण्डिङ कीमत	(रु./किग्रा.)	***
क्षति मार्जिन	(रु./किग्रा.)	***
क्षति मार्जिन	(अम.डा./किग्रा.)	***
क्षति मार्जिन	%	***
क्षति मार्जिन(रेज)	%	5-15

ट. प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतीकरण

88. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतीकरण

क. पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पूर्वव्यापी आधार पर किया जाए।

ख. पाटनरोधी शुल्क अमरीकी डालर/किग्रा. में शुल्क के रूप में अभिव्यक्त, पाटनरोधी शुल्क की केवल निर्धारित प्रमाणा (शुल्क का निर्धारित तरीका) के रूप में ही अधिरोपित की जाए।

ग. निर्धारित गैर-क्षतिकारी कीमत न्यून है और यह भारतीय उत्पादकों के विधिक हितों की रक्षा करने के लिए अपर्याप्त है। घरेलू उद्योग यह नोट करता है कि मौजूदा कानून घरेलू उद्योग के इस आधारभूत अधिकार के विरुद्ध है कि अनुचित पाटित आयातों के विरुद्ध संरक्षण की मांग की जाए।

घ. एचओसीएल ने इस याचिका का समर्थन किया है। शुरुआत के पश्चात एचओसीएल ने कीमत निर्धारण और क्षति की पूरी जानकारी दी है। डब्ल्यूटीओ के स्पष्टतः यह धारित किया है कि 'घरेलू उद्योग' शब्द का आशय 'समग्र रूप से घरेलू उत्पादक' होगा और केवल उस स्थिति में, जहाँ घरेलू उत्पादकों के बारे में समग्र की जाएगी।

रूप से जानकारी उपलब्ध नहीं है, निर्दिष्ट प्राधिकारी को भारतीय उत्पादन के बड़े भाग पर विचार करने की अनुमति है। पुनर्श्च, यदि एचओसीएल आंकड़ों को पृथक कर दिया जाता है, तो भी केवल जीएनवीएफसी से संबंधित आकड़ भी क्षति दर्शाते हैं।

३. घरेलू उद्योग ने दोहराया है कि ट्रैकेम को अलग से पाठन मार्जिन नहीं दिया जा सकता और यह प्रस्तुत किया कि यदि संबंधित उत्पादक सहयोग नहीं देता है तो निर्यात कीमत का भी निर्धारण नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी के विगत निर्णय का उल्लेख किया जिसमें प्राधिकारी ने सभी संबंधित पक्षकारों के पर्याप्त प्रत्युत्तर के अभाव में व्यक्तिगत पाठन मार्जिन मना कर दिया है।

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

89. अन्य हितबद्ध पक्षकारां द्वारा प्रकटन पश्चात् प्रस्तुतीकरण

अन-पश्चात-प्रस्तु

क. ट्रेडकेम ने यूरोप से भारत को समुद्रपारीय भाड़े, समुद्रपारीय बीमा और निर्यात कीमत को फैक्टरी-बाह्य स्तर पर लाने की साख-लागत के आधार पर समायोजन की सूचना दी है और इसने अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर में यह भी स्पष्ट किया है कि सम्बद्ध वस्तुएं सीधे यूरोप से भारत आती हैं। अतः, प्राधिकारी को निर्यात कीमत को फैक्टरी-बाह्य स्तर पर आसानी से निर्धारण कर, लेना चाहिए।

ख. प्राधिकारी ने विगत मामलों में व्यक्तगत पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है जिनमें किसी भी उत्पादक ने सहयोग नहीं किया और इसलिए इसे बर्तमान मामले में भी ऐसा ही करना चाहिए।

ग. याचिकाकर्ता के निष्पादन में जॉच की अवधि के पश्चात अत्यधिक सुधार आया है। यदि घरेलू उद्योग को जॉच की अवधि के दौरान कथित पाटित आयातों से पीड़ित थी, तो घरेलू उद्योग को क्षति कम से कम बर्तमान पाटमरीधी जॉच शुरू होने तक जारी रहनी चाहिए थी।

घ. प्राधिकारी का यह निष्कर्ष उपित नहीं है कि कीमत-कटौती के बजाय जॉच की अवधि के लिए ही संगत नहीं है। प्रकटन विवरण में वर्ष 2006-07 के लिए खुलासा की गई सीआईएफ कीमत के अनुसार वर्ष 2006-07 के लिए कीमत-कटौती सकारात्मक नहीं हो सकती है। अतः प्राधिकारी घरेलू उद्योग की एनएसआर के साथ-साथ लैण्डिङ कीमत का परिकल्पन करने पर पन्दित्यार करेगी। क्षति अवधि (जॉच अवधि के सिवाय) के दौरान नकारात्मक कीमत कटौती का आशय है कि

लैण्ड कीमत, घरेलू उद्योग के एनएसआर से अधिक है। तब घरेलू उद्योग का क्षति अवधि के दौरान, जब लैण्ड कीमत में आयातकों के प्रचलित माजिन में जोड़ने के पश्चात बैंचमार्क कीमतें एनएसआर से उच्चतर स्तर पर थीं, कीमतें बढ़ाने के लिए किसने रोका था।

ड. एचओसीएल ने, उसी उत्पाद संबंधी एसएसआर निष्कर्ष में पहले से ही गुमराज किया है। यह उल्लेख किया गया कि एचओसीएल द्वारा दिया गया आरटीआई डिल प्लाट जीवाब केवल एक एनिलिन प्लाट के बारे में था जबकि कम्पनी के दीने एनिलिन के डिल प्लाट हैं, जबकि एचओसीएल वेबसाइट के अनुसार उनका एनिलिन वेनिमोण के बारे में लिए रासायनिक महाराष्ट्र में केवल एक प्लाट है। यहां पर्याप्त है कि यहां पर्याप्त है कि एसा लगता है कि याचिकाकर्ता ने एनएसआर की पूरी रिपोर्ट नहीं दी है। उसी धूम मिक्की उत्पाद के सबध में यूएसए और जापान के विरुद्ध अधिकार जाच, जिसकी जाच नहीं किया है। अवधि के 9 माह चालू जाय अवधि में शामिल हैं और इसके अन्तिम निष्कर्ष में 5 ग्रामी डिल प्राधिकारी ने यह मिर्धारित किया है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि ओस्त एनएसआर, एनआईपी से उच्चतर रहा है। इसके अतिरिक्त कोई तो उल्लेख कीमत कटौती एवं हासि प्रभाव नहीं था। निल प्लाट का उपयोग किया गया है। यदि घरेलू उद्योग को क्षति का एकमात्र कारण आया तो ही है तो एसएसआर जाच

की जाँच अवधि, जिसमें आयातों में वृद्धि हुई थी, में घरेलू उद्योग के निष्पादन में और अधिक कमी आनी चाहिए थी। एसएसआर, जाँच अवधि के दौरान (अर्थात् २५ अक्टूबर, २००९ से सितम्बर, २०१० तक) घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत इकाई के ताज़ागतीय रूप से एनएसआर से कम थी और जाँच की अवधि का यह काल मन्दी के तुरन्त बाद

का समय था (अर्थात् अप्रैल, 2009 से सितम्बर, 2009)। ऐसा मामला होते हुए नायक के अधिकारी को जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के एनआईपी और के ८०-१०००१ एनएसआर के बीच मासिक तुलना करना अपेक्षित है ताकि यह मुद्रित हो सके कि वैशिक मंदी की अवधि के पश्चात घरेलू उद्योग को क्षति जारी रही क्योंकि कालाघाट जांच अवधि के पहले छह माह वैशिक मंदी से प्रभावित रहे। ११५ गली निवासी जांच सम्बद्ध वर्जन की आयत की मात्र में जांच की अवधि के पश्चात पर्याप्त वृद्धि हुई है यादिकार्ता के निष्पादन से जबरदस्त वृद्धि करने और बाजार विकास से जुड़ बचने के अनुसरण में बेनजीन के मूल्यों में वृद्धि स्थिर रखने के लिए संदर्भ की मत आधार पर प्रट्टन्सेडी शुल्क अधिसूचित किया जाना चाहिए। ११६ यह एक निर्णय के लिए है जो कि जांच कार्य के लिए इस विषय को है नियन्त्रित रखने के लिए इसकी होनी चाहिए कानूनी रूप से अधिक दूरी की जाए।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

90. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों की प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के लिए संगत पाई गई सीमा तक, निम्नवत जांच की:

क. ड्रेडकेम के लिए पृथक पाटन मार्जिन के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इयू में संबंधित उत्पादक से प्रश्नावली प्रत्युत्तर न आने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया गया। किसी भी स्थिति में प्राधिकारी इस बात को स्वीकार करने एवं सराहने में अक्षम है कि इयू में संबंधित उत्पादक ने प्राधिकारी को सहयोग क्यों नहीं दिया और संगत जानकारी क्यों नहीं प्रदान की। फैक्टरी-बाह्य कीमत का निर्धारण करने के लिए व्यापारी न तो प्रचलित है और न ही उसने सभी अपेक्षित जानकारी दी है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यात से जुड़े कुछ व्यापार उस व्यापारी ने नहीं किए हैं और वे संबंधित उत्पादक द्वारा किए गए हैं। चूंकि संबंधित उत्पादक ने प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है इसलिए संबंधित उत्पादक से पर्याप्त सहजाने के बिना फैक्टरी-बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण करना सम्भव नहीं है। प्राधिकारी ने विगत में भी पृथक पृथक पाटन मार्जिन का निर्धारण करने से मना कर दिया है जब भारत को निर्यात की सम्पूर्ण श्रृंखला प्राधिकारी के समक्ष नहीं थी।

ख. जहां तक याचिकाकर्ता के पीओआई पश्चात निष्पादन का सबध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटन अथवा क्षति विश्लेषण करने के लिए पीओआई पश्चात के आंकड़ों पर विचार नहीं किया जाता है।

ग. वर्ष 2006-07 के दौरान आयातों की लैण्डिंग कीमत और क्षति अवधि के दौरान कीमत-कटौती की संगतता के संबंध में दिए गए तर्कों के बारे में, वर्ष 2006-07 के दौरान कीमत-कटौती परिकलनों की पुनः समीक्षा की गई और उसमें आवश्यक संशोधन किए गए। वर्तमान मामले में स्पष्टतः जाँच की अवधि में कीमत-कटौती सकारात्मक है। यह भी देखा जाता है कि वर्ष 2008-09 के अपवाद का छोड़कर, जब कीमत-कटौती नकारात्मक थी तो आयातों की मात्रा न्यून थी और जब कीमत-कटौती सकारात्मक थी तो आयातों की मात्रा अधिक थी। वर्ष 2008-09 की अवधि पर भन्दी का प्रभाव था। यह स्पष्टतः स्थापित करता है कि आयात में वृद्धि न्यून कीमतों के कारण हुई। प्राधिकारी फूँ: नोट करते हैं कि इसने कई मामलों में केवल जाँच की अवधि में कीमत कटौती का निर्धारण किया है और इन मामलों में क्षति का सकारात्मक निष्कर्ष रिकॉर्ड किया है।

घ. एचओसीएल के साथ एनिलिन प्लाट की सख्त्या के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार द्वारा विश्वास किए गए आरटीआई उत्तर से यह स्पष्ट उल्लेख होता है कि प्रदान कराई गई जानकारी "प्लाट न्यू" के बारे में है। प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि एचओसीएल के तीन एनिलिन प्लाट हैं जो विभिन्न समयों पर शुरू किए गए हैं। कृष्ण निर्णय के कानून विभिन्न तिथि के प्रबोधक प्राप्त होती है। ड. कृष्ण निवल बिक्री प्राप्ति की अल्प सिपोर्टिंग के आरोप के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसने घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारित करने के लिए कंपनी की लेखा-पुस्तिका से सत्यापित आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी मुझे नोट करते हैं कि दोनों मामलों में जांच की अवधि अलग-अलग है और वर्तमान जांच की जांच अवधि के संबंध में प्रस्तुत जानकारी पर विचार करना अपेक्षित है। एक बार जांच अवधि निर्धारित हो जाने के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि उह घरेलू उद्योग की जांच अवधि के लिए और जांच अवधि तकी के निष्पादन पर विचार करें। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग पर पारिस्थितिक आयातों की कीमत और मात्रा संबंधी विपरीत प्रभावों को पाया है। इसका फल प्राप्त होने के लिए वर्तमान जांच अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन के संबंध में केवल यह नियम कि सनसेट समीक्षा जांच अवधि के दौरान निवल बिक्री प्राप्ति घरेलू उद्योग की गैर-कानूनी कीमत से कम था, का आशय यह नहीं है कि प्राधिकारी वर्तमान मामले में निवल बिक्री प्राप्ति और गैर-कानूनी कीमत के बीच मासिक तुलना पर एकसाथ विचार करे। और न ही इससे यह सिद्ध होता है कि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। सनसेट समीक्षा मामले में, यह पाया जाया कि आयातों की मात्रा न्यून थी और यह आयात जांच की अवधि के कछु चनिन्दा महीनों में ही किए गए और अतः संबंधित महीनों की कीमतों के बीच तुलना करना आवश्यक था। वर्तमान मामले में संपर्ण जांच-अवधि में आयात किए गए और घरेलू उद्योग ने बिक्री कीमत के विपरीत नियम के अनुरूप विकास की है। इसकी विवरणीयता की जांच अवधि का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के पश्चात संबद्ध क्षेत्रों की उत्पादन लागत और आयात कीमत दोनों में वृद्धि हुई है और अतः संदर्भ कीमत के रूप में

पाठनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश से पाठनरोधी शुल्क का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा और इससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होगी।

91. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग को पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार से होने वाली क्षति का उप-शमन करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित की जा सके जो देश के आम हित में हो। पाटनरोधी उपाय का अधिरापण संबद्ध देश से किसी भी भी हाल में आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगा और अतः उपभोक्ताओं को ठत्तादं की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

92. यह अभिज्ञाते किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से संबद्ध वस्तु का प्रयोग करके उत्पादों का विनिर्माण करने के कीमत वस्तु को प्रभावित करेगा और इसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। तथापि, पाटनरोधी उपाय करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी खासकर

तब, जब पाटनरोधी शुल्क की वसूली घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का निराकरण करने के लिए आवश्यक राशि तक प्रतिबंधित कर दी जाए। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय करने से पाटित व्यवहार द्वारा अनुचित लाभ अर्जन दूर होगा और यह घरेलू उद्योग को पतन से बचाएगा तथा संबंद वस्तु को उपभोक्ताओं को व्यापक पसंद की उपलब्धता देगा।

क विचाराधान उत्पाद का सबद्ध दश से इसक सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत को निर्यात किया गया है, जिससे इस उत्पाद का पाठन हुआ। घरेलू उद्योग को संबद्ध एवं अवृस्तु के बरेतमें औतिक क्षति हुई। यह भौतिक क्षति संबद्ध देश से सुनित आयातों के द्वारा उत्पादकारण हुई है। इस क्षति के लिए आंट ने इसका जनकी उत्तर नहीं दिया है। इसके लिए उत्पादकों द्वारा जनकी उत्तर नहीं दिया जाता है। इसकी वजह से भारतीय उत्पादकों को अपनी सिफारिश

94. प्राधिकारी यह जाट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारी को छह दिनों तक इसकी सूचना दी गई तथा निर्यातकों, आशालक्षकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सादत दी गई। क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक जानकारी देने के लिए स्थापित अवसर दिया गया। पाटन, क्षति और उनका कारणात्मक संबंध की पाटनरोधी नियमावली के अनुसार जांच शुरू करने और आयोजित करने और इन पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति तथा सकारात्मक पाटन स्थापित करने के पश्चात प्राधिकारी का विचार है कि पाटन और परिपासी क्षति को दर करने के लिए निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपण करना अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी सम्बद्ध वस्तु का सम्बद्ध देश से यहाँ उल्लिखित इसके सभी फार्मों एवं तरीकों से आयातों पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करना आवश्यक समझते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं।

95. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए न्यूनतर शुल्क नियम के संबंध में, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति मार्जिन के न्यूनतर के समरूप निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदुसार यूरोपियन यूनियन में उत्पादित या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर, केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की तारीख से अधोलिखित तालिका के कॉलम 9 में विनिर्धारित राशि के अनुरूप निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की जाती है।

शाल्क तालिका

क्र.सं.	उप-शीर्षक	प्रस्तुति/विवरण	विनिर्देशन	उद्धम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2921.41	एनेलिन	कोई	यूरोपियन यूनियन	यूरोपियन यूनियन	कोई	कोई	110.72	प्रति मी.एक्स. डा.	अमे. डा.
2.	2921.41	एनेलिन	कोई	यूरोपियन यूनियन (संघीय संस्थान)	यूरोपियन यूनियन (संघीय संस्थान)	कोई	कोई	110.72	प्रति मी.एक्स. डा.	अमे. डा.
3.	2921.41	एनेलिन	कोई	कोई	यूरोपियन यूनियन	कोई	कोई	110.72	प्रति मी.एक्स. डा.	अमे. डा.

96. इस अधिसूचना के तीउद्देश्यों के इलिए आयातों का अपहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अन्तर्गत सीमाशुल्क द्वारा अधिनिर्धारित आकलनीय मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अन्तर्गत शुल्कों के अतिरिक्त सभी सीमाशुल्क शामिल होंगे।

97. केन्द्र सरकार के इस आदेश के विरुद्ध सीमाशूल्क ट्रैफिक अधिनियम के अनुसार सीमाशूल्क, उत्पाद कर और संवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है।

के नाम प्रियांशुर, कि वहां के लोकों ने उन्हें प्रसन्नता से ग्रहण किया था। विजय लक्ष्मी जोशी, निदिष्ट प्राधिकारी एवं विद्युत प्रियांशुर कानूनी अधिकार के प्रस्तुत के लिये लक्ष्मी जोशी, निदिष्ट प्राधिकारी एवं विद्युत प्रियांशुर के नाम लिया गया था। विजय लक्ष्मी जोशी कि विद्युत प्रियांशुर ने विद्युत इकान नामीकरण के बारे में संज्ञान एवं विद्युत प्रियांशुर के नाम लक्ष्मी जोशी के नाम लक्ष्मी जोशी के नाम लिया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

Subject : Anti Dumping Investigation concerning import of Aniline originating in or exported from the European Union-reg.

No. 14/39/2010-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time, and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof:

A. BACKGROUND

- Whereas M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers Co. Ltd. on behalf of the domestic industry (hereinafter referred to as the Applicant/Petitioner) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules or the AD Rules), alleging dumping of Aniline (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from the European Union (hereinafter also referred to as the Subject Territory). M/s Hindustan Organics Chemicals Ltd. had expressly supported the petition. The Delegation of European Commission in India representing the EU in India was notified about the receipt of fully documented application as per Rule 5(5).
- The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicant to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the Subject Territory. The Authority notified the Delegation of European Commission in India representing the EU in India about the receipt of the application claiming, inter alia, allegations of dumping and consequent injury to the domestic industry before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules. The Authority issued a public notice No. 14/39/2010 dated 20th December, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the Subject Territory, in accordance with the Rule 6(1) of the AD Rules to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE FOLLOWED IN THE INVESTIGATION

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation.

- a. The Designated Authority under the above mentioned Rule received a written application filed by M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers Co. Ltd. (GNFC) on behalf of the domestic industry, alleging the dumping of Aniline originating in or exported from the European Union. M/s Hindustan Organics Chemicals Ltd. had expressly supported the petition.
- b. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicant to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the subject Territory.
- c. The Authority, in accordance with sub-Rule 5(5) of the AD Rules, notified to the Delegation of European Commission in India about the receipt of information alleging dumping of the subject goods from the subject Territory before proceeding to initiate the investigation.
- d. The Authority issued a Public Notice No.14/39/2010 dated 20th December, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods Aniline originating in or exported from the Subject Territory, in accordance with the sub-Rule 6(1) of the AD Rules to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry. The date to complete the investigation was extended by the Central Government to 19th April, 2012.
- e. Investigation was carried out for the period of investigation (POI) starting from 1st April, 2009 to 30th June, 2010 (15 months). The examination of trends, in the context of injury analysis, covered the periods 2006-07, 2007-08, 2008-09 and the POI.
- f. The Authority forwarded a copy of the Public Notice to all the known exporters whose details were made available by the Applicant and the industry Associations and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.
- g. The Authority also forwarded a copy of the Public Notice to all the known importers of the subject goods in India from the subject Territory countries and advised them to submit their views in writing within forty days from the date of issuance of the letter.
- h. The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters and the Delegation of European Commission in India in accordance with Rule 6 (3) of the AD Rules. A copy of the Application was also provided to other interested parties, wherever requested.
- i. The Authority sent Exporter Questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in the subject Territory in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

S.No.	Name of the Company
1.	BASF AG, Germany
2.	Huntsman Advanced Materials, Belgium
3.	Huntsman Petrochemicals, United Kingdom
4.	BorsodChem MCHZ, s.r.o., Czech Republic
5.	Moravské Chemické Závody Ostrava, Czech Republic
6.	M/s Bayers AG, Germany
7.	Dow Chemical Company, Germany
8.	Hoechst AG, Germany

j. In response to the above Notification, the following interested party filed its response:

S.No.	Name of the Company
1.	Tradechem International FZE, Dubai

k. Importer Questionnaire was sent to the following known importers and consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules.

S.No.	Name of the Company
1.	Aarti Industries Ltd., Mumbai
2.	Abir Chemicals Ltd, Ahmedabad
3.	Alginates Allied chemicals P Ltd, Badlapur
4.	Alpha Dyes & Chemicals, Ahmedabad
5.	Asiatic Color Chem Industries, Ahmedabad
6.	Atul Ltd, Gujarat
7.	AurobindoPharma Ltd, Hyderabad
8.	Bayer India Ltd, Mumbai
9.	Industrial Solvents & Chemicals Ltd, Mumbai
10.	International dyestuff Industries , Vadodara
11.	Jay Chemical Industries Ltd, Ahmedabad
12.	Mangalam Drugs & Organics, Mumbai
13.	Metrochem Industries Ltd, Ahmedabad
14.	NOCIL, Mumbai
15.	NutanDyechem, Surat
16.	Beck (India) Ltd, Pune
17.	BhangeriaDyechem Ltd, Mumbai
18.	Diamond Dyechem, Mumbai
19.	Ganesh Chemicals Industries, Mumbai
20.	Hindustan Incs& Resins Ltd, Vapi
21.	Padnasara Industries Ltd, Padasara
22.	Ravi Dyeware Co. Ltd, Mumbai
23.	Roop Dyes & industries
24.	Schenectady Beck (India) Ltd, Mumbai
25.	SonkamalEnterprise P Ltd., Mumbai
26.	VipulDyechem Ltd., Mumbai

- I. In response to the Notification, response has been received from the following importers/consumers:
 - i. Kutch Chemicals Industries Ltd
 - ii. Ravi Dyeware Co. Ltd
 - iii. BASF India Ltd
 - iv. Dyestuffs Manufacturer's Association
 - v. M/s Industrial Solvents and Chemicals (P) Ltd
 - vi. NOCIL Ltd
- m. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- n. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties.
- o. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange the details of imports of subject goods for the period of investigation and the preceding three years.
- p. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the applicant on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain as to whether the anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove the injury to the Domestic Industry.
- q. The Authority held an Oral Hearing on 30th November, 2011 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance with Rule 6(6). The parties who attended the oral hearing were advised to file written submissions of the information presented orally. The interested parties were allowed to present rebuttal arguments/rejoinders on the views/information presented by other interested parties. The Designated Authority has considered submissions received from various interested parties appropriately.
- r. Arguments raised and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority.
- s. In accordance with Rule 16 of Rules Supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties vide Disclosure Statement dated 20th March, 2012 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in this Final FindingsNotification.

t. *** in this Final Findings Notification represents information furnished by the applicant on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

C. **PRODUCT UNDER CONSIDERATION & LIKE ARTICLE**

C.1. **Views of the Domestic Industry**

4. Following issues were raised by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article:

- Aniline is classified under Chapter 29 of the Customs tariff Act, 1975, under customs sub-heading No. 2921.41 under the category of Organic Chemicals.
- Aniline is a transparent, oily liquid and is a primary amine compound. Its color transforms to light pale yellow liquid when freshly distilled. Its color darkens when exposed to light or air. Aniline is a basic organic chemical, essential for vital industries such as drugs, pharmaceuticals, dyes and dye intermediates. Aniline is also used in some other industries such as rubber chemicals, explosives, resins, etc. The major raw materials used to produce Aniline are Benzene, Hydrogen and Concentrated Nitric Acid. Nitrobenzene, an intermediate for the production of Aniline, is produced by the nitration of Benzene. Thereafter, Aniline is produced by the catalytic reduction of nitrobenzene with hydrogen.
- Aniline is used as a vulcanization agent, accelerator, and antioxidant. It is used in photographic chemicals, dyes & dye intermediates, pharmaceutical, isocyanides. Aniline is also used in making of explosives, pesticides, insecticides, herbicides, fungicides, etc. The subject good is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading no. 2921.41. However, customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
- There is no difference in Aniline produced by the domestic industry and imported from the subject Territory. Aniline produced by the domestic industry and imported from the subject Territory is comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology (followed by most of the producers the world over), functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used the two interchangeably. Aniline produced by the petitioners and imported from subject Territory is like article.

C.2. **Views of Exporters, Importers, Consumers, and Other Interested Parties**

5. None of the interested parties contested the claim of the petitioner that the subject goods imported from the subject Territory are like articles in respect of the goods produced and sold by the domestic industry in the Territory.

C.3. **Examination By The Authority**

6. The following is the examination by the Authority:

a. The product under consideration in the present investigation is “Aniline” which is also known as “Aniline Oil” originating in or exported from European Union. Aniline is a transparent, oily liquid and is a primary amine compound. Its color transforms to light pale yellow liquid when freshly distilled. Its color darkens when exposed to light or air. Aniline is a basic organic chemical, essential for vital industries such as drugs, pharmaceuticals, dyes and dye intermediates. Aniline finds its application in some other industries as well such as rubber chemicals, explosives, resins, etc. Aniline is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading no. 2921.41. However, customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation. This information has been correlated with the information provided by responding foreign producers.

b. Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules specifies that like article means an article, which is identical and alike in all respects to the product under investigation or in the absence of such an article, another article having characteristics closely resembling that of the article under examination.

c. The petitioner has claimed that the goods produced by them are like articles to the goods originating in or exported from the subject Territory. None of the opposing interested parties has raised any objection with regard to the scope of the product under consideration and the like article. The Authority notes that Aniline produced by the domestic industry has characteristics which are similar to those of Aniline imported from the subject Territory.

d. In view of the above, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the goods imported from the subject Territory in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The Authority also holds that the subject goods are classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading no. 2921.41 but the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

D. STANDING OF THE PETITIONER AS DOMESTIC INDUSTRY

D.1. Views of the Domestic Industry

7. Following are the views of the domestic industry with regard to the standing:

a. The petition was filed by Gujarat Narmada Valley Fertilizers Co. Ltd. The data was also filed by M/s Hindustan Organics Chemicals Ltd., thereby, expressly supporting the petition. There are two other companies in India who had created capacity for production of Aniline, namely, M/s Anirox Pigments Ltd. and M/s Luna Chemicals Ltd.

b. Production of petitioner along-with the HOCL constitutes a major proportion in Indian production and, therefore, petitioner should be treated as “domestic industry” within the meaning of the Rules.

- c. Reference by the importers/consumers/other interested parties to the WTO report in the matter concerning Mexico – Steel Pipes and Tubes from Guatemala is misplaced. Facts and circumstances of the said case are absolutely different.
- d. In the said investigation, Investigation Authority has determined domestic industry for the producers, which account for 88% of the production of product concerned, whereas injury examination has been conducted for the producers which account for 53% of the product concerned.
- e. In fact, in the very same decision, the WTO has held that in practice, an Investigating Authority could have partial information to start an investigation, which might then be supplemented as the investigation proceeds.
- f. In the facts of the present case, Gujarat Narmada Valley Fertilizers Company Limited filed the petition, which was supported by Hindustan Organic Chemicals Company Limited. The said fact has been stated in the Initiation Notification itself.

D.2. Views of the importers, consumers and other interested parties

- 8. Following are the views of the importer, consumers and other interested parties with regard to the standing:
 - a. HOCL's name does not appear in the petition and, therefore, HOCL could not be part of the domestic industry in the Initiation Notification.
 - b. Data of HOCL cannot be accepted as the domestic industry, as the Initiation Notification states that applicant shall constitute the domestic industry, which in the instant case is Gujarat Narmada Valley Fertilizers Company Limited.
 - c. The domestic industry is fixed at the start of the investigation and it should continue to be so throughout and should not be interfered with. Reliance is placed on WTO decision in the matter concerning Mexico Anti-Dumping Duties – Steel Pipes and Tubes from Guatemala.

D.3. Examination by the Authority

- 9. Rule 2(b) of the Anti dumping Rules, as amended on 1.12.2011, defines the domestic industry as under:-

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

10. The petition is filed by M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers Company Limited. There are only three other known producers of the subject goods in India, namely, M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd., Anirox Pigments Limited, and Luna Chemicals Ltd. M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited has expressly supported the petition and has submitted all the relevant information in this respect with the Authority. Petitioner has claimed that M/s Anirox Pigments Ltd. has stopped its production. According to the information provided in the application, the production of Gujarat Narmada Valley Fertilizers Company Limited and HOCL constitutes "a major proportion" of total Indian production during the period of investigation.

11. The Authority, therefore, holds that the petitioner satisfies standing and the petitioner constitutes "domestic industry" within the meaning of Rule 2(b) and Rule 5 (3) (a) of the Anti-Dumping Rules.

12. The Authority notes that it is claimed by the interested parties that petition has been filed by GNFC and based on their petition, the Authority initiated the investigation. Therefore, subsequently, the composition of the domestic industry cannot change and the Authority needs to proceed with the investigation based on the domestic industry determined in the Initiation Notification. Therefore, HOCL should not be included in the purview of the domestic industry. The Authority notes that in this regard, reference has been given to the decision of WTO in the matter concerning Mexico – Anti -dumping duties on steel pipes and tubes from Guatemala, and it is claimed that it has been upheld by the WTO that domestic industry once defined in the initiation notification, cannot be changed subsequently.

13. With regard to the above, the Authority notes that the WTO decision in the matter of Mexico – anti-dumping duties on Steel Pipes and Tubes from Guatemala- referred by the interested parties does not state that the investigating authorities are prevented from calling information from those domestic producers who had supported the petition at the stage of initiation and using those information for the analysis"

Other issues

14. Issues raised by the domestic industry:

- The applicants request for the retrospective imposition of anti-dumping duty as there is a long history of dumping.
- The same can be observed from the previous record of dumping of subject goods and then subsequent imposition of anti dumping duty. Further, dumping from Japan and USA, which resulted in imposition of anti dumping duties (which was further extended for a period of five years) further establishes dumping of the product.
- Further, the non-cooperation of the exporters establishes the fact that they are resorting to dumping. The importers are also well aware about the dumping practice.

15. Issues raised by other interested parties

- Common POI should be taken for parallel investigation, i.e., current investigation and Sun Set Review (SSR) investigation of imports from USA and Japan, as has been done by the DA in the past.

- b. Excessive confidentiality:-Petitioners have not disclosed Formats A to E under the anti dumping application Proforma, source of freight and other overhead expenses for calculating Normal Value, market share of the petitioner and other domestic producers, sales policy details as required by Question 14B and price underselling as required by Proforma IV A.
- c. HOCL information/data should not be considered for injury analysis after more than ten months of deadline.
- d. Exact calculation of the normal value has been concealed under confidentiality, preventing from making any comment.
- e. Transaction wise import data provided in the petition is different from the one which is considered in injury analysis.
- f. The Authority failed to see the accuracy and adequacy of the data prior to initiation of the investigation.
- g. The invoice date and the date of shipment for the subject goods are separated by a considerable time difference due to which comparison between landed value and domestic prices is bound to be distorted.
- h. Export price for determining landed value of the imported goods is calculated on the basis of the price reflected on the invoice date. Therefore, the domestic selling price to be compared to the landed value should also relate to the corresponding time period as the invoice date, and not the domestic prices prevailing at the time of shipment of the subject goods.
- i. Conversely, if the prices of DI are considered on the date on which the subject goods are imported, then such domestic prices would be based on a subsequent time period when different prices may be prevailing than the prices prevailing on the date of invoice.
- j. Petitioner's request of retrospective imposition of anti-dumping duty is not justified as the two mandatory pre-conditions for the imposition of duty, as laid in the Section 9A (3) of the Act, are not satisfied, i.e., (i) history of dumping and (ii) massive dumping in short time period and the injury caused is so severe that it is likely to undermine the remedial effect of the AD Duty.
- k. The claim of common producers in the USA and Europe is wrong and without any evidence.
- l. POI is incorrect as the case was initiated in December, 2010 with a POI ending five months back, which will never result in correct analysis. No reason has been given for deviating from the normal rule of taking 12 months as the POI and taking 15 months as the POI in the instant case. Further economic slowdown has also not been considered while taking the POI.
- m. Two separate POIs in two investigations in respect of the same subject goods initiated on the same day, has been done without any justification.
- n. Petitioner is trying to divert the issue, which is whether the DA can treat M/s HOCL as a supporter without any request made by any party. The initiation notification is

the outcome of well documented application by the party seeking such initiation and not vice versa.

Examination by the Authority

16. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties. The Authority notes that the claim of confidentiality in the application in the present case is consistent with the practice being followed by the Authority. The interested parties have not established any specific instances of incorrect claim of confidentiality. The Authority has allowed claims of confidentiality with regard to information which is by nature confidential, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor and because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information. The Authority has required interested parties providing confidential information to furnish non confidential summaries. Therefore, on being satisfied with regard to claim on confidentiality, the Authority allows the same.
17. With regard to common producers in the USA and European Union, the Authority notes that there are producers who are having production facilities simultaneously in the USA and European Union. With regard to support of HOCL, the Authority notes that the fact of support by HOCL has been stated in the initiation notification itself. Therefore, there is no merit in the argument. The Authority is required to determine scope of the domestic industry at each stage of the proceedings. In fact, one of the purposes of initiation of investigation is to call relevant information from all relevant parties, and if one or more other domestic producer files information before the Authority after initiation of investigations, the Authority is required to include such information for the purpose of assessment of injury. The Authority further notes that anti-dumping investigation is a process where quality and quantity of evidence improves as the investigation progresses.

E. DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

18. Issues raised by the Domestic Industry

- a. Petitioner has not been able to get any evidence of price in the domestic market of European Union nor could evidence be procured for the export price from EU to third countries.
- b. The normal value has been constructed for all exporters/producers from EU.
- c. In view of significant differences in costs and prices with time period, normal value has been determined by considering multiple averages.
- d. Export price has been determined considering the volume and value of imports for the period of investigation as per the data released by secondary source, i.e., International Business information Service, Mumbai. Considering the significant difference in prices

with time period, the petitioner has determined the export price separately for each of the month for the period of investigation.

19. Issues raised by the interested parties including importers, consumers in India

- a. Petitioner has chosen to construct normal value regardless of exports to third countries. From the said information concerning exports to third countries, it is clear that the total average export price is much lesser than the price at which the PUC is exported to India.
- b. Exports to India are made at prices comparable to those of developing countries like Indonesia and, in fact, at prices higher than those of other economies such as Mexico, Russia and South Africa, clearly indicating that there is no dumping of the PUC in the POI.
- c. EU has been exporting the subject goods to other countries at a weighted average price of 875 Euro/MT and at the same time has exported to India at 936 Euro/MT which does not conclude dumping from any angle. Exports to India are made at prices comparable to those to the developing countries.
- d. The data has been worked upon the basis of monthly pricing of benzene to arrive at the cost of production, which eventually leads to calculate the NV and compare the same to the export price but the same yardstick has not been applied while conducting the injury analysis. Therefore the methodology adopted ought to be rejected.
- e. There is no provision under the law which says that the individual dumping margin should be determined only when the concerned exporter and producer (both) have cooperated in the investigation and in the absence of this, the submissions can be rejected. Individual rate of dumping margin is required to be determined for every known exporter or producer in terms of Rule 17 (3). Section 9A (6A) also uses the phrase 'producers or exporters'. Tradechem is a known exporter and individual dumping margin must be determined for them.
- f. In the past DGAD cases, namely, 8-Hydroxyquinolin from China; Acetone from EU, Chinese Taipei, Singapore, South Africa & USA; Silk fabrics; Phenol, the DGAD determined individual rate for the exporter (trader) even when producer did not respond. In the case of carbon black, separate dumping margin was determined for the trader even when it did not cooperate completely.
- g. The export price information presented by Tradechem cannot be rejected as also held by WTO Panel in US-Steel Plate from India .
- h. Facts available should not be applicable to Tradechem as it has not violated Art 6.8 of WTO Agreement. Further, the requirements enshrined in para 3 of Annexure II are fully met. Therefore, there is no ground to exclude the information presented by the exporter.

Examination by the Authority

20. The Authority notes that the trader Tradechem from Dubai has filed response and claimed individual dumping margin. The Authority further notes that in its response, the trader categorically stated that the company purchases Aniline from many countries including

Europe and sells it to Indian customers. For determination of dumping margin, the Authority requires normal value and export price. As already mentioned that there is no response from the European Union. In the absence of response from the producers from the European Union, the Authority could not determine export price at ex-factory level to compare it with the normal value, and thus, the dumping margin cannot be determined. Mere CIF export price is not sufficient to determine dumping margin. With regard to reference of other past cases, the Authority notes that reference of these cases is misplaced and facts and circumstances of these cases are different from the present case.

21. With regard to determination of normal value as per exports to third countries, the Authority notes that *prima facie* determination of claim of normal value in the petition by the petitioner is different from the final determination by the Authority. For final determination, the Authority requires a verifiable information with regard to domestic sales, i.e., in the ordinary course of trade, which is not available in this case as no exporter/producer has preferred cooperation with the Authority.

E.1. Normal Value

22. Under Section 9 A (1) (c) of the Customs Tariff Act, 1975 'Normal Value' in relation to an article means:-
 - (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely trans shipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

23. The Authority notes that none of the producers/exporters of the subject goods in the subject territory has responded to the Designated Authority. There has been only one response filed by M/s Tradechem International FZE, Dubai. It is noted that the company is a trader, who sources the subject goods from various countries including European Union and exports the same to India. Further, there is no response by the producers from European Union whose subject goods have been exported by Tradechem International FZE, Dubai. Therefore, the export chain of the transaction is not complete and thus, the Authority holds that the information filed by Tradechem International FZE, Dubai will not be taken into consideration. The Authority, therefore, determines Normal Value as per facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. The Authority notes that the information/evidences regarding the prices of the subject goods in the domestic market of the subject Territory could not be procured by the Petitioner as no information is available in the public domain. Further, petitioner could not gather information pertaining to the export price from Europe to third countries. Also, the volume of exports to third countries could not be considered low due to lack of any published information with regard to month-wise exports from Europe to third countries. Further, in the absence of details of cost of production, administrative, selling and general costs of the subject goods, it is not possible for the Authority to determine whether the exports to third countries were in the ordinary course of trade. The normal value in the subject Territory, therefore, is determined considering the constructed value.

24. The normal value for the Aniline imported from EU has been constructed based on the following principles.

- (a) The best utilisation norms of the most efficient domestic producer for the major raw materials Benzene, CNA and Hydrogen have been considered.
- (b) Based on the average price published by ICIS LOR (Europe) the international prices during POI for Benzene has been considered. In the absence of international price of Hydrogen and CNA, efficient producer's rate has been adopted. Cost of other minor raw materials has been considered as per most efficient domestic producer's cost.
- (c) Cost of utilities, conversion cost, SGA expenses and interest have been considered at the level of the most efficient domestic producer.
- (d) 5% of cost of sales excluding interest has been allowed towards reasonable profit.

Accordingly, the weighted average normal value of Aniline from European Union is determined at US\$1.20 per kg.

E.2. Export Price

25. Under Section 9 A (1) (b) of the Customs Tariff Act, 1975, 'Export Price' in relation to an article means:

(b) "export price", in relation to an article, means the price of the article exported from the exporting country or territory and in cases where there is no export price or where the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported articles are first resold to an independent buyer or if the article is not resold to an independent buyer, or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as may be determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

26. In view of no response from any of the exporters/producers of the subject goods from the subject Territory, export price is determined considering volume and value of imports for the period of investigation as per DGCIS data. Adjustments have been made on account of Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Port Expenses, Inland Freight and Bank Charges. Export Price so arrived at comes to USD 1.02 per kg.

E.3. Dumping Margin

27. Under Section 9 A (1) (a) of the Customs Tariff Act, 1975, the calculation of 'Margin of Dumping' is given as follows—

(a) "margin of dumping", in relation to an article, means the difference between its export price and its normal value;

28. The Rules relating to comparison of normal value and export price provides as follows:

"While arriving at the margin of dumping Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. A comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level and in respect of sales made and as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case on its merits, for differences which occur price comparability including differences in conditions and terms and sales, taxation, levels of trade quantities, physical characteristics and any other differences which are demonstrated to affect price comparability."

29. For the purpose of fair comparison between normal value and export price, the Authority takes into account the information furnished by the petitioner and other published information available with the Authority. The normal value and export price as detailed above are at ex-works level. Dumping Margin is given in the table below:

Source	Normal Value US\$/KG	Export Price US\$/KG	Dumping Margin US\$/ KG	Dumping Margin%
European Union – All producers and exporters	1.20	1.02	0.18	17%

30. The dumping margins so determined are significant and above de-minimis level.

F. ASSESSMENT OF INJURY AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK

F.1 Submissions made by domestic industry

31. Following submissions are made by the domestic Industry:

- a. There has been increase in demand of the product throughout the period of injury, except for the year 2008-09. The reason behind such decline in demand is global melt down situation.
- b. Sales of Domestic Industry show a declining trend. The slight increase in the sales volume in the POI is the result of recovery after the global recession.
- c. The imports from the subject Territory have increased in absolute terms and in relation to the total imports in India. The imports from the subject Territory have also increased in relation to production of product under consideration in India.
- d. The market share of imports from the subject Territory has shown significant increase, especially during the POI where it has increased three times from the base year and that of the domestic industry has shown a decline. The subject Territory has captured the share of the domestic industry.
- e. The imports from the subject Territory are undercutting the prices of the Domestic Industry in the Indian market. The selling prices of the Domestic Industry have declined over the injury period. The imports are, thus, resulting in price depression in the market. Further, the cost of production increased over the period, whereas the selling price of the Domestic Industry declined. The imports were, thus, suppressing the prices of the Domestic Industry in the market.
- f. Despite the stable capacity being maintained by the Domestic Industry, production of the Domestic Industry and consequently the capacity utilization has declined. Domestic Industry has suffered in terms of production, solely as a result of decline in sales volume caused by increase in imports.
- g. Profits of the Domestic Industry have significantly declined. The increase or reduction in selling price is disproportionate to the costs. Consequently, profitability of the Domestic Industry has shown significant deterioration.
- h. As a result of decline in profitability, performance of the Domestic Industry deteriorated in terms of Return of Investment and cash flow.
- i. The inventories with the Domestic Industry have increased significantly in the POI in comparison with the previous years.
- j. The domestic industry has been faced with negative growth in most of the injury parameters.

- k. Even when the domestic industry has been offering the product at sub-optimal prices, it is faced with declining sales.
- l. The applicants request for the retrospective imposition of anti-dumping duty as there is a long history of dumping in respect of the subject goods. The same can be observed from the previous record of dumping of subject goods and then subsequent imposition of anti dumping duty. Further, dumping from Japan and USA, which resulted in imposition of anti-dumping duties (which was further extended for a period of five years) further establishes dumping of the product. Further, non-cooperation of the exporters establishes the fact that they are resorting to dumping. The importers are also well aware about the dumping practice.
- m. Even when the domestic industry has been offering the product at sub-optimal prices, it is faced with declining sales.
- n. With regard to the allegation of sales through trader, it is submitted that the domestic industry sells the material directly as also through traders and it is up to the customers to decide how they would like to source the material.

F.2 Issues raised by importers and consumers

32. Following submissions are made by the importers and consumers:

- i. Domestic sales of the petitioner are through intermediary entity, viz, Tradex Corporation. Price at which the petitioner sells its product cannot be representative of the price of Domestic Industry since it is not the price at which the final consumer buys the product under consideration.
- ii. Although the volume of imports from the subject Territory has increased, the volume of total imports remained same in the Territory.
- iii. There is no price undercutting over the period. In fact, petitioner has sold at a lower price than the landed value of the imports. The domestic industry prices have remained constant over the injury period and, therefore, no effect of imports on prices is proved.
- iv. Demand has remained constant, whereas the indigenous sale of the PUC has not declined. The sales of the domestic industry have increased over the period of injury. Share of imports have also remained constant. Therefore, market share of the domestic industry has not been affected.
- v. The reduction in the capacity utilization is due to annual shut down of the plant each year. Capacity utilization, in fact, improved in the POI.
- vi. There is a decline in the share of production of the DI in the year 2008-09, whereas the share of production of other domestic manufacturers has increased by 12%.
- vii. The profitability has not suffered to the segment to which the PUC belongs, whereas other segments of the Petitioner have suffered.
- viii. There has been a significant decline in the exports of the subject goods.
- ix. The increase in inventories is due to the plant shut down and decline in export sales.

- x. Sales of the subject goods have improved in proportion to the increase in production by the Domestic Industry.
- xi. There is a 30% growth in production from base year to the POI. Growth in indigenous sales has also shown an increase by 24%. Growth in PBIT is by 30%.
- xii. Claim of the Domestic Industry is not justified as the prices of benzene have remained constant over the period of injury whereas NSR of the Domestic industry has improved. Majority of the injury period has witnessed a negative price undercutting. Even in the POI, a marginal difference of 5% has been observed.
- xiii. While calculating the cost of production and the return on capital employed, the Authority must consider the best performance of the domestic industry in the three previous years.
- xiv. Decline in the capacity utilization of the domestic industry is due to the economic slowdown, and this situation is well accepted in the annual reports of the company.
- xv. Decline in capacity utilization is also due to the decline in export volumes.
- xvi. Since first half of the period 2009-10 was affected by economic slowdown, the analysis of sales, imports and demand should be made separately for the first half of the period 2009-10.
- xvii. Landed price of the subject goods always remained higher than the selling price of the Domestic Industry.
- xviii. Decline in profit is caused by higher decline in selling price of the Domestic Industry in comparison to cost while landed price is much higher than NSR in spite of reduction in custom duty and, thus, no correlation between landed price and profit of Domestic Industry.
- xix. During the POI, undercutting was insignificant but before the POI undercutting was significantly negative while profit of the Domestic Industry was at low level in 2008-09. Therefore, profitability of Domestic Industry has not been impacted from price undercutting over the injury period.
- xx. Lower sales realization is due to low benzene prices and thus not attributed to dumped imports.
- xxi. High inventory of subject goods was due to annual contracts signed by GNFC with buyers in June'10 which used to be signed in April'10. This affected the sales volume during the first quarter of 2010-2011. Inventory and sales volume should be verified for the post period as well.
- xxii. Claim of increase in the cost of production is incorrect as the cost of benzene has reduced which constitutes almost 60-65% of the total cost of Aniline.
- xxiii. There are evidences of unfair trade practices started by the petitioner. It sold the subject good in India at significant low price as compared to the weighted average landed price of imports from all countries and as well as price of other domestic producers.
- xxiv. Concentrated nitric acid, one of the major raw materials used for the production of Aniline is produced by the petitioner and is then transferred for production of Aniline. The petitioner has claimed increase in cost of production, whereas the raw material price has not increased in the POI as compared to the base year. Therefore, it is doubtful

whether the petitioner transfers the raw material on cost or market price in order to arrive at Aniline cost.

- xxv. Data submitted by petitioners in two separate investigations of the same subject goods is different in terms of costs of sales and profits but ROI is same inspite of change in PBT.
- xxvi. The annual reports of the Petitioner reveal several other factors responsible for injury to the domestic industry such as poor off-take of downstream products, global meltdown and recession, lower prices of benzene, economic slowdown, lower realization and high stock owing to Annual Shutdown.
- xxvii. Only volume information of the supporter is taken into consideration for evaluating the factors concerning volume injury analysis. If the price data of the supporter is also taken into consideration, then there would be no difference between the terms 'applicant' and 'supporter'.
- xxviii. The performance of domestic industry has drastically improved post POI which indicates that the injury period and the POI only showed a dip in the performance caused by the global recession and not by any alleged dumping.
- xxix. Capacity utilization has remained within the band of 100% throughout the injury period except 2008-09 when there was a dip because of the plant shut down and global recession.
- xxx. Post POI figures reveal that the injury was temporary. GNFC's Annual Report states that sales have increased due to improved market conditions after global meltdown. The capacity utilization based on the new prospects from their Annual Report for 2010-2011 is at 114%. Sales production ratio is 100%.
- xxxi. Fall in total sales cannot be attributed to imports but to the export sales.
- xxxii. Loss of market share is not linked to the dumped imports but is on account of HOCL which has maintained low capacity utilization which forced imports of the subject goods.
- xxxiii. Petitioner sells the PUC via trader and the supporter directly sells them to the consumer. Therefore, the price at which petitioner sells to the intermediary cannot be considered to be representative of the price of the DI since it is not the price at which consumers buy the PUC.
- xxxiv. NSR for petitioner is Rs 60/kg, but the trader sells it at much higher price. (confidential)
- xxxv. Tradex, the intermediary, prices its sales on the basis of the ongoing international price at the time of delivery whereas the importer/consumer takes delivery of the goods from the date of booking to around 2 months. Therefore, to that extent the injury margin needs to be accordingly calculated.
- xxxvi. There is growth in all major parameters as shown in the Proforma IV-A.
- xxxvii. According to Annexure III, while calculating cost of production and return on capital employed, the DA must consider the best performance of the DI. And therefore, the DA should determine the POCE accordingly.
- xxxviii. CNA, critical raw material for Aniline, is captively consumed. Applicant admitted that it is used as the by-product. Therefore, its cost should be taken on minimal basis and not the market price as proposed by the Petitioner. If the transfer price of CNA is adopted based

on the market price, then capital employed pertaining to CNA should not be added to the capital employed for Aniline.

xxxix. DA should examine books of records maintained by the applicant and take the captive consumption prices and not the market value.

xl. In the instant case for a single manufacturer, i.e., GNFC, the cost of manufacturing or the market price (whichever is less) of the intermediate, i.e., CNA, should be considered for computing the total cost of finished product and if market price is considered, then the capital employed for that intermediate should not form part of the total capital employed of the finished product.

xli. No causal link established as injury is caused due to shut down of plant, global recession, low prize of benzene etc.

xlii. Petitioner cannot meet demand, and the performance of petitioner after POI has improved significantly.

xliii. HOCL data needs to be completely rejected as they failed in fulfilling the requirements of timeline and relevant authorisations in relation to participation in the investigation. The analysis of HOCL data would show that the injury, if any, suffered by them is absolutely due to their internal reason and injury suffered for other reasons should not be attributed to dumping

xliv. Petitioner has claimed achievable capacity on the basis of best production of one month, which is incorrect. The injury to the petitioner should be determined based on the full year capacity which should be further based on the annual report.

xlv. Capacity and production volumes for domestic and export operations are not segregated in the injury analysis.

xlii. During the injury period, except for the POI, selling price of the petitioner was significantly lower than the landed price as well as the selling price of other domestic producers. Lower selling price in 2006-07, 2007-08 and 2008-09 was not due to dumping by foreign producers. Therefore, no question of dumping arises. No reason has been provided by the DI for selling below the landed price, when there was no alleged dumping from the subject Territory.

xlvii. No basis for information on raw material is provided by the petitioner. Increase in selling price was more than increase in raw material price of the subject goods.

xlviii. Since the first six months of the POI were affected due to economic slowdown, post POI data becomes relevant.

xlix. Selling price of petitioner is consistently lower than other domestic producers and foreign producers despite of existing ADD in force in respect of other countries. The reason for such low selling must be examined in detail.

l. Duty should not be imposed retrospectively as the pre-conditions under section 9A(3) are not met. There is no history of dumping in respect of subject Territory. The onus to prove the same is on the domestic industry. Dumping margin determined by petitioner is not based on evidence. It is highly inflated due to higher normal value and lower export price due to unrealistic adjustments. Hence no case of massive dumping is made out.

- li. Petitioner has modified the purview of the DI in the written submission as against the petition.
- lii. Injury information/data should not be considered in the examination of injury on the basis of claims made by the petitioner on behalf of HOCL. Righteous treatment of such exceptional situation is inalienable in the present investigations as the same has a tremendous impact on establishing alleged injury to the domestic industry as has been held by the EC.
- liii. Capacity utilization of the petitioner (GNVFC) has been maintained at 101% level in the POI while HOCL's capacity utilization is at 21% to 28% level in the entire injury period.
- liv. If both GNVFC and HOCL are competitive and facing problems only from dumping, then their cost and consequently their profit should not vary so much. The heavy losses of HOCL are on account of factors other than imports, let alone dumping.
- lv. There is no causal link between the injuries suffered by HOCL and alleged dumped imports. GNVFC's data alone would show that performance of domestic industry was moderate in the POI and it actually sky-rocketed in the post POI period, i.e., 2010-11. Inclusion of HOCL data would distort the entire picture as their injury is due to some internal reasons.
- lvi. Since Concentrated Nitric Acid is produced by the petitioner in their factory, the rate of Concentrated Nitric Acid should be considered at cost. ICIS LOR reports are generated on weekly basis. Therefore, the Authority should consider rate of benzene from weekly reports and finance cost should be considered based on actual of petitioner instead of estimation.
- lvii. There is no concept of actual achievable capacity as has been made out by the petitioner and, therefore, this logic merits no consideration.
- lviii. It is an admitted fact that exports of the petitioner reduced considerably throughout the injury period which consequently affected the operation of the petitioner, this did not affect the domestic operations which are the subject matter of injury. This issue needs to be analysed in detail by the DA.
- lix. Post POI data must be considered as has been done in the case of NFY.
- lx. Cost of benzene has also declined in the POI. Then how domestic industry claims increase in the cost of production.
- lxi. Domestic industry has claimed two different costs of sales and profits with same ROI even on the change in PBIT in two separate investigations.
- lxii. As the landed value of imports is calculated on the basis of the price as reflected in the invoice date, the domestic selling price to be compared with the landed value should also relate to the invoice date and not to the date of shipment. The same principle has been followed in Polypropylene Case.
- lxiii. Proforma IV B shows no injury during the entire injury period. The negative price undercutting during the base year ensures the same.
- lxiv. The annual report of the petitioner provides information to the contrary as there have been improvements in the performance.

- lxv. The injury claimed by the domestic industry is unjustified. Petition is silent on the material factors like NIP and underselling.
- lxvi. The sales of the domestic industry are made through an intermediate trader. Therefore, its price should not be considered as the price of the domestic industry. The injury due to low price is due to its sales to intermediate and not due to imports. It is a self-inflicted injury.
- lxvii. NIP and degree of underselling has not been disclosed to other parties.

F.3 Examination of Injury and Causal Link by the Authority:

33. The Authority notes that various interested parties argued that no injury has been caused to the domestic industry due to the imports from subject territory. However, examination of various parameters by the Authority established that there is injury to the domestic industry. The Authority notes that opposing parties have argued no injury considering single producer information only. However, none of the parties has been able to put forward any legal basis as to why only one producer's data should be considered for injury. The Authority notes that some of the interested parties have referred to WTO decision in the matter concerning Mexico – anti-dumping duties on steel pipes and tubes from Guatemala. The said decision clearly holds that an investigating authority could have partial information to start an investigation, which might then be supplemented as the investigation proceeds and injury examination should be done for the defined domestic industry and not just major proportion of defined domestic industry. In this case, HOCL supported the petition at the time of initiation of the investigation as mentioned in the initiation notification and subsequently, the company furnished complete costing information, which has been verified by the Authority. The Authority, therefore, does not find any merit in the argument of the interested parties.

34. Regarding post period of investigation performance, the Authority notes that in the post period of investigation, all other parameters would have changed, which can be examined and investigated only through a complete investigation. Interested parties have right to apply for a review under Rule 23. In the present investigation, post period of investigation performance has no relevance.

35. With regard to the claim of some interested parties that CNA is a by-product, the Authority notes that CNA is not produced as a by-product by GNFC, whereas Hydrogen is produced from the waste gas. With regard to the claim that petitioner cannot meet demand, the Authority notes that it is not pre-requisite that the petitioner should meet the demand of product in India. With regard to sales through trader by the domestic industry, the Authority notes that comparison has been done at same level of trade.

36. With regard to post period of investigation data considered in NFY investigation, the Authority notes that the reference is misplaced as the said investigation was a sunset review investigation, wherein the Authority examined likelihood of injury.

37. With regard to 100% plant utilization by the domestic industry, the Authority notes that domestic industry as a whole is not utilizing its 100% capacity. With regard to 100% plant utilization by one of the constituent of domestic industry also, Authority notes that claim is not supported by the law. Rules provide for actual and potential decline in sales, production, capacity

utilization etc. The fact is that the said constituent of domestic industry also faced decline in production.

38. With regard to decline in exports, the Authority notes that there is decline in exports of the domestic industry. However, domestic industry has furnished segregated information on injury relating to the domestic performance and injury caused in the domestic market due to dumping of the subject goods from the subject Territory. Thus, the injury being claimed is the injury caused due to the performance in the domestic market alone. Further, increase in imports is much more than decline in exports.

39. With regard to negative price undercutting, the Authority notes that price undercutting is relevant only for the period of investigation. Negative price undercutting shows that there has been no injury in the past as undercutting was negative, whereas positive undercutting in the period of investigation shows that landed price is forcing the domestic industry to reduce its prices.

40. Rule 11 of Anti-Dumping Rules read with Annexure-II provides that injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on the prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

41. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry, para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments."

42. The Authority notes that the margin of dumping and quantum of imports from the subject Territory are more than the limit prescribed above. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered further indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, magnitude and margin of dumping etc., in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.

45. The Authority notes that Annexure II of AD Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products. While examining the volume effect of the dumped imports, the Authority is

required to examine as to whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to price effect of dumped imports, the Authority is required to examine as to whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increase which would have otherwise occurred to a significant degree.

46. As regards the impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of AD Rules states as under: "The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

47. Production of petitioner constitutes a major proportion in Indian production. Petitioner constitutes domestic industry. Thus, the Authority has considered petitioner as the domestic industry.

48. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments of the interested parties.

F.4. Volume Effect of Dumped Imports

49. With regard to volume of the dumped imports, it has been examined that whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the anti dumping Rules provides as under:

"While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India"

F.5. Import Volumes and Share of the Subject Territory

50. The volume of imports from the subject Territory has been as under:

	2006-07	2007-08	2008-09	P O I- 15M	P O I Annualized
Subject Countries/Territory-EU	7,006	1,821	8,874	23,394	18,715
Countries - Attracting Duty	6,108	6,074	-	1,497	1,198
Other – Countries	17	10,799	-	23	18
Total	13,131	18,694	8,874	24,914	19,931
Market Share					
Subject Countries/Territory-EU	53.36%	9.74%	100.00%	93.90%	93.90%

Countries - Attracting Duty	46.52%	32.49%	0.00%	6.01%	6.01%
Other – Countries	0.13%	57.77%	0.00%	0.09%	0.09%
Indian production	47,377	47,981	39,100	56,775	45,420
Imports from EU in relation to Indian production	15%	4%	26%	46%	46%
Demand in India.	58,393	65,082	47,636	78,246	62,597
Imports in relation to Demand in India from subject country	12%	3%	19%	30%	30%

51. The Authority notes that:

- Imports of the subject goods from the subject territory have increased significantly over the injury period in absolute terms and in relation to production and consumption in the Territory.
- The imports from other countries have declined significantly and now almost ceased completely in the period of investigation.
- The market share in imports from the subject Territory has increased over the entire injury period except for 2008-09 and reached to a very significant level of 30% in demand in India.

F.6. Assessment of Demand & Market Share

52. Demand of the subject good has been determined by adding domestic sales of the domestic industry, domestic sales of the other Indian producers and imports from all countries. The Authority notes that the demand for the subject goods has grown from base year to period of investigation.

	2006-07	2007-08	2008-09	P O I- 15M	P O I Annualized
Domestic industry	45,262	43,388	33,562	47,333	37,866
Other Indian Producers	0	3000	5200	6000	4800
Subject Territory	7,006	1,821	8,874	23,394	18,715
Other Countries- attracting Duty	6,108	6,074	-	1,497	1,198
Other Countries	17	10,799	-	23	18
Demand	58,393	65,082	47,636	78,246	62,597
Market Share					
Domestic industry	78%	67%	70%	60%	60%
Other Indian Producers	0%	5%	11%	8%	8%
Subject Countries	12%	3%	19%	30%	30%
Other Countries-attracting Duty	10%	9%	0%	2%	2%
Other Countries	0.03%	16.59%	0.00%	0.03%	0.03%

53. From the above table, the Authority notes the following:

- a. The demand of the subject goods has increased over the injury period in absolute terms except for the year 2008-09. After 2008-09, the demand increased again in the period of investigation.
- b. The market share of the domestic industry has declined significantly during the POI.
- c. The market share of the subject Territory has increased significantly and more than doubled in the period of investigation.
- d. The market share of the other countries attracting anti dumping duty has declined drastically.

54. The Authority notes that there has been significant decline in import prices from EU as is evident from the table below, which led to increase in imports from European Union and EU captured significant market share.

	2006-07	2007-08	2008-09	POI-13M
Imports from European Union in MT	7,006	1,821	8,874	23,394
Value of imports in Rs. Lacs	4,148.26	1,078.61	5,733.37	12,532.66
Average price Rs./MT	59,210	59,234	64,612	53,573
Average price Rs./MT – Indexed	100	100	109	90

F.7. Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry & factors affecting prices

55. With regard to the effect of dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of Rule 18, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of like product in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred to a significant degree.

56. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry from the subject Territory has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the weighted average cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the Domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject Territory.

F.8. Price Undercutting & Underselling

57. Price undercutting has been determined by comparing the landed value of dumped imports from the subject countries over the entire period of investigation with the net sales realization of the domestic industry for the same period. For this purpose, landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty and cess to the value reported in the IBIS data of import prices from the subject Territory.

58. For the purpose of price underselling, the landed price of the imports from subject Territory has been compared with the non-injurious price of the domestic industry determined for the POI.

Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI
Net Sales Realization	Rs. Kg	63.94	59.64	63.29	60.79
Landed price of imports	Rs. Kg	66.52	63.86	69.65	57.75
Price undercutting	Rs. Kg	(2.58)	(4.22)	(6.36)	3.04
Price undercutting	%				5.26
Non Injurious price	Rs. Kg				63.04
Price underselling	Rs. Kg				5.29
Price underselling	%				9.16

59. From the above table, the Authority notes that the landed value of dumped imports of subject goods from the subject Territory was undercutting the domestic prices significantly during the POI. Further, the landed value of the subject goods from the subject territory was also significantly below the non-injurious price of the domestic industry.

F.9. Price suppression and depression effects of the dumped imports:

60. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices, the Authority has determined whether the effect of such imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred to a significant degree. For this purpose, the import prices of subject goods have been compared with the trends in cost of production and selling price of the domestic industry.

		2006-07	2007-08	2008-09	POI-15M
Cost of sales	Rs./MT	62,799	61,988	69,508	66,860
Index	Trend	100	99	111	106
Selling Price	Rs./MT	63,944	59,636	63,294	60,792
Index	Trend	100	93	99	95
Profit/Loss	Rs./MT	1,144	(2,352)	(6,214)	(6,068)
Index	Trend	100	(206)	(543)	(530)

61. The Authority notes the following:

- The cost of production of the domestic industry increased during the injury period. Though, the same declined in period of investigation compared to previous year, yet the cost of production of the period of investigation is more than the base year.
- Inspite of increase in cost of production, the selling price of the domestic industry declined as compared to the base year.
- The movement in selling price of the subject good shows that while during the POI the cost of production went up by about 6%; the selling price, on the contrary, declined by 5% as compared to the injury period.

iv. The domestic industry made profits in the base year, but the loss has increased in the POI.

62. The above analysis indicates that the domestic industry had decreased its selling price in spite of increase in the cost of production of the subject goods. It, therefore, appears that the low prices of the dumped imports have forced the domestic industry to reduce its prices in the POI.

F.10. Examination of other Injury Parameters

63. The above analysis shows that the dumped imports have adverse volume and price effect on the domestic industry in terms of increase in volume of dumped imports both in absolute terms and market share. The price undercutting in respect of subject good has been positive and significant. The movement in selling price has not been commensurate with the corresponding movement in the cost of production. The domestic industry has suffered both volume and price injury.

64. Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity, factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

a. Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales of the Domestic Industry

65. The production, capacity and capacity utilization of the domestic industry is as below:

	2006-07	2007-08	2008-09	P O I- 15M	P O I Annualized
Capacity MT	60,100	60,100	60,100	75,125	60,100
Production MT	47,377	44,981	33,900	50,775	40,620
Sales MT	45,262	43,388	33,562	47,333	37,866
Capacity Utilization %	79%	75%	56%	68%	68%

66. The Authority notes that-

- The capacity of domestic industry remained same over the years.
- In spite of sufficient demand in the country, due to availability of dumped imports from European Union, the sales of the domestic industry declined over the injury period resulting in decline in production and capacity utilization of the domestic industry.

Though the production increased in the period of investigation compared to 2008-09, still it remained lower than earlier levels.

b. Profit, Return on Investment & Cash Flow

67. The following table provides the information with respect to the profit, return on capital and cash flow of the domestic industry:

		2006-07	2007-08	2008-09	P O I-15M
Cost of Production	Rs./MT	62,799	61,988	69,508	66,860
Index	Trend	100	99	111	106
Selling Price	Rs./MT	63,944	59,636	63,294	60,792
Index	Trend	100	93	99	95
Profit before Interest & Tax	Rs./MT	1,380	(2,261)	(5,953)	(5,529)
Index	Trend	100	(206)	(543)	(530)
Cash Profit	Rs. Lacs	1,150	(576)	(1,581)	(2,276)
Index	Trend	100	(50)	(137)	(198)
Return on Investment	%	3	-5	-11	-15
Index	Index	100	(167)	(367)	(533)
Capital Employed	Rs. Lacs	19872	20718	18127	14501

68. The Authority notes the following:

- i. The cost of production of the domestic industry increased during the injury period. Though, the same declined in the period of investigation as compared to previous year, yet the cost of production in the period of investigation is more than the base year.
- ii. Inspite of increase in the cost of production, the selling price of the domestic industry declined throughout the injury period.
- iii. The movement in the selling price of the subject goods shows that while during the POI, the cost of production went up by about 6%, the selling price declined by 5%.
- iv. While the domestic industry made profits in base year, it had incurred losses since 2007-08.
- v. Domestic industry could not increase its selling price even when there was a significant increase in the cost of sales resulting in losses.
- vi. Return on investment and cash profits have also declined and they became negative from 2007-08 onwards.
- vii. It has been argued by the interested parties that there is no injury to GNFC and that injury to HOCL is due to others factors. The Authority examined the data of GNFC separately and noted that there has been significant impact of dumped imports on performance of GNFC as well and return on capital employed of the GNFC also declined significantly.

c. Productivity

69. The following table provides the information with respect to the productivity of the domestic industry:

		2006-07	2007-08	2008-09	POI Annualised
Productivity per day	MT/Day	144	136	103	123
Productivity per Employee	MT/No	201	187	145	174
Index		100	93	72	86

70. The Authority notes that the productivity of the domestic industry on per day basis as well as per employee basis declined during the injury period. Though, there is increase in productivity in the period of investigation compared to 2008-09, the same still remained less than the level of the base year.

d. Employment & Wages

71. The information with regard to the employment and wages of the domestic industry is provided in the table below:

		2006-07	2007-08	2008-09	POI-15 Months	POI Annualised
Employment	No.	236	241	233	234	119
Index		100	102	99	99	99
Wages	Rs. Lacs	782	758	856	1270	1016
Index		100	97	109	-	130

72. It is noted that employment does not show any significant change as the constituents of domestic industry are multi-product companies. However, there was increase in wages during the period of investigation.

e. Inventories

73. The table below shows the level of inventory with the Domestic Industry:

		2006-07	2007-08	2008-09	POI-15M
Inventories	MT	517	790	807	3,647
Index		100	153	156	705
Inventories for days sales	No. of days	3.72	6.18	8.34	33.65
Index		100	166	224	905

74. The Authority notes that the inventories with the Domestic Industry have increased significantly in the POI in comparison with the earlier years. Consequent to the decline in the sales volume, inventories of the Domestic Industry have increased significantly. The Authority also examined inventory for number of days sales and noted that the inventory

which was just for less than 4 days in the base year, increased to more than a month in the period of investigation.

f. Magnitude of Dumping

75. The Authority notes that the magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry and it shows in the present case that the dumping margins determined against the subject Territory, for the POI, are significant.

g. Growth

76. Growth of the Domestic Industry in terms of the majority of parameters such as production, capacity utilization, domestic sales, inventories, market share, profits, return on investments, cash profits, and productivity is negative. Production declined by 14% compared to the base year, sales declined by 16% over the base year, imports from subject Territory increased by 165% over base year, profitability declined by 630% over base year, cash profit declined by 298%, return on investment declined significantly from positive to negative.

G. Conclusion on Injury

77. On the injury front, the Authority concludes as under:

- i. Imports of the product under consideration from the subject Territory increased in absolute terms and in relation to production and consumption in India.
- ii. Imports are undercutting the prices of the Domestic Industry to a significant extent.
- iii. Imports are depressing the prices of the Domestic Industry and preventing the price increase that is caused due to the effect of dumping.
- iv. Performance of the Domestic Industry has deteriorated in terms of production, capacity utilization, domestic sales, inventories, market share, profits, return on investment, cash profits, productivity, etc.
- v. It would not be appropriate to consider the trends of employment and wages as the petitioner is a multi-product company and employment and wages are not solely dependent on the performance of the subject goods.

78. The Authority, hereby, conclude that there is material injury to the domestic industry due to the imports of subject goods from the subject Territory.

H. CAUSAL LINK

79. The following establishes the causal link:

- i. The import of Aniline from the subject Territory has increased in absolute terms.
- ii. The imports from the other countries are insignificant when compared to total imports to India from the European Union. Further, imports from Japan and USA are already attracting anti-dumping duties and sunset review investigation is in progress. The

imports from other countries are, therefore, not causing injury to the domestic industry.

- iii. The demand for the subject product does not show any contraction. In fact, domestic industry has sufficient capacity to meet demand. However, due to dumping, the domestic industry was not able to sell its product and, therefore, production declined and inventory increased.
- iv. In establishing that the material injury to the domestic industry has been caused by the imports from the subject Territory, the Authority notes that the increase in market share of imports from European Union prevented the domestic industry from increasing its sales and market share inspite of increase in domestic demand. The decline in sales resulted in decline in production and consequent reduction in capacity utilization of the domestic industry. The domestic industry failed to match the landed price of the imported product on account of the rise in prices of the raw material required for the manufacture of Aniline. Imports from the subject Territory had the effect of undercutting the prices of the domestic product, forcing the domestic industry to maintain their price levels below the reasonable level. Resultantly, the domestic industry incurred losses. The material injury to the domestic industry was, therefore, caused by the dumped imports from the said Territory.

I. Examination of Other Known Factors

Development of technology

80. The Authority notes that none of the interested parties raised any argument in this regard. It is, therefore, noted that the technology as also production process for producing the subject goods is fairly stabilized and there is no injury to the domestic industry on this account.

Export performance

81. The Authority notes that there is decline in exports of the domestic industry. However, domestic industry has furnished segregated information on injury suffered by it in the domestic market due to dumping of the subject goods from the subject Territory. Thus, the injury being claimed by the domestic industry is the injury caused due to performance in the domestic market alone.

82. No other factor which could have possibly caused injury to the domestic industry has been brought to the knowledge of the Authority.

Conclusion on Causation

83. Significant increase in the volume of dumped imports has resulted in decline in the market share of the domestic industry. It is further seen that decline in market share of domestic industry as a consequence of increase in market share of subject imports from subject countries resulted in decline of the domestic industry sales inspite of significant demand. As a result, the production and consequently the capacity utilization of the domestic industry declined.

84. Further, significant price undercutting caused by dumped imports prevented the domestic industry from increasing its prices to the extent of increase in costs. Resultantly, profit, cash flow and return on investment of the domestic industry deteriorated in the POI.

85. The Authority, therefore, concludes that the dumped imports originating in or exported from the subject Territory have caused material injury to the domestic industry within the meaning of Rule 11 of Anti-dumping Rules and Article 3.5 of the Agreement of Antidumping.

Magnitude of Injury Margin

86. The non-injurious price determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports for the determination of injury margin. The weighted average landed price of the exports from the subject Territory and the injury margins have been worked out as follows.

Injury Margin calculations

87. The Authority has determined injury margin considering non-injurious price of the subject goods produced for domestic sales by the domestic industry and the landed price of the subject goods imported from subject territory. Non-injurious price has been determined in accordance with Annexure III of the AD Rules. All captive inputs have been considered at their cost and in addition return has been provided @22% on the average net fixed assets relating to the captive input. With regard to the allegation made by interested parties that the cost of production of HOCL is higher due to other reasons, the Authority has considered the cost of production of HOCL at 100% capacity utilization of its plants of the subject goods and captive intermediates in order to exclude injury if any due to other factors. Non-injurious price and injury margin determined are as shown below:

NIP	(Rs/Kg)	63.04
Landed Price	(Rs/Kg)	57.75
Injury Margin	(Rs/Kg)	5.29
Injury Margin	(USD/kg)	0.11072
Injury Margin	%	9.16%
Injury Margin (Range)	%	5 - 15

J. Post Disclosure Statement submissions

88. Post Disclosure Statement submissions by the Domestic Industry

- Imposition of anti dumping duty should be done on retrospective basis.
- Anti dumping duty may be imposed only as fixed quantum of anti dumping duty (fixed form of duty), expressed as duty in US\$/kg.
- Non injurious price determined is low and insufficient to protect legitimate interests of Indian producers. The domestic industry notes that the present law itself is against the basic right of domestic industry to seek protection against unfair dumped imports.
- HOCL had supported the petition. Post initiation, HOC provided complete costing and injury information. The WTO has clearly held that the word "domestic industry" shall

mean "domestic producers as a whole" and only in a situation where information for domestic producers as a whole is not available, the Designated Authority is permitted to consider a major proportion of Indian production. Further even if HOCL data is segregated, data relating to GNVFC alone also shows injury.

e. Domestic industry reiterated that individual dumping margin cannot be given to Tradechem and submitted that even export price cannot be determined if the producer concerned has not cooperated. The domestic industry has referred to past decisions of the Authority wherein the Authority has denied individual dumping margin in view of lack of sufficient response from all connected parties.

89. Post Disclosure Statement submissions by other Interested Parties

a. Tradechem has reported adjustments on account of overseas freight from Europe to India, overseas insurance and credit cost for arriving at export price at ex-factory level and it has also clarified in the questionnaire response that the subject goods move directly from Europe to India. Therefore, the Authority should determine easily export price at ex-factory level.

b. Authority has determined individual dumping margin in the past cases wherein no producers had cooperated and it should, therefore, do the same in the instant case.

c. Performance of petitioner has significantly improved after POI. If the domestic industry was suffering from alleged dumped imports in the POI, injury to the domestic industry should have continued after POI at least till current AD investigations had been initiated.

d. The Authority's inference that price-undercutting is relevant only for the period of investigation is not correct. The price undercutting for 2006-07 cannot be positive as per CIF prices for 2006-07 are disclosed in disclosure statement. Therefore, the Authority may kindly revisit to calculation of landed price vis-à-vis NSR of domestic industry. There was negative price-undercutting during the injury period (excepting POI) meaning that landed price higher than NSR of domestic industry. Then what prevented the domestic industry from raising its price during the injury period when the bench-mark prices in the form of landed price added with importers margin prevailed at much higher level than NSR.

e. HOCL has already misled as in the SSR Finding on same product. It has been stated that RTI reply given by HOCL was only in respect of one Aniline plant whereas the company has three Aniline plants whereas as per HOCL's website they have only one plant for manufacturing Aniline in Rasayani, Maharashtra.

f. There appears to be a case of under-reporting of NSR on the part of petitioner. The latest investigation on the same product against USA and Japan, 9 months of the POI thereof overlaps with the current POI and in its final finding, Authority determined that domestic industry has not suffered any injury because the average NSR has been higher than NIP. Further, there was no price suppression and depression effect.

g. If the imports are the only reason for injury to the domestic industry, performance of domestic industry should have been further declined in the POI of SSR investigation wherein imports has increased. Non-injurious price of domestic industry was lower than its NSR during SSR POI (i.e. October 2009 to September 2010) and this period POI was just after the period of recession i.e. April 2009 to September 2009. Such being the case, the Authority is required to do monthly comparison between NIP and NSR of the domestic industry during POI, to ensure, injury to the domestic industry is

continued after global recession period as the first six month of POI affected by global recession.

h. Anti-dumping duty on a reference price basis should be imposed for the reason that import price of subject goods significantly increased after POI, robust growth in performance of petitioner and to maintain stability on the value addition of Benzene in pursuance of avoiding market distortion.

Examination by the Authority

90. Submissions made by the interested parties have been examined by the Authority hereunder to the extent these are found relevant to the present investigation:

a. As regards separate dumping margin for Tradechem, the Authority notes that no cogent reasons have been given for lack of questionnaire response from the producer concerned in EU. In any case, the Authority is unable to accept and appreciate why the producer concerned in EU could not have cooperated with the Authority and provided relevant information. The Trader is neither privy nor has provided all information required for determination of ex-factory export price. The Authority notes that some of the expenses associated with exports are not incurred by the trader and are incurred by the producer concerned. Since producer concerned has not cooperated with the Authority, it is not possible to determine ex-factory export price without cooperation from the producer concerned. The Authority has denied individual dumping margin determination in the past also when the complete chain for exports to India is not before the Authority.

b. As regards the issue of petitioner's performance in post-POI is concerned, the Authority notes that post-POI data is not considered for undertaking either dumping or material injury analysis.

c. With regard to the arguments relating to landed price of imports during 2006-07 and relevance of price undercutting over the injury period, the calculations of price undercutting during 2006-07 have been reviewed again and necessary corrections made. In the present case, admittedly, the price undercutting in the period of investigation is positive. It is also seen that with the exception of 2008-09, the import volumes were low when price undercutting was negative and import volumes were high when the price undercutting was positive. The period 2008-09 was impacted due to recession. This clearly establishes that the increase in imports is due to lower import prices. The Authority further notes that it has determined price undercutting only in the period of investigation in a number of cases and recorded the positive finding of injury in these cases.

d. With regard to the number of Aniline plants with HOCL, the Authority notes that the RTI reply relied upon by the interested party clearly states that the information furnished is in respect of "Plant-III". The Authority further notes that there are three Aniline plants with HOCL commissioned at different points of time.

e. With regard to the allegation of under-reporting of net sales realization, the Authority notes that it has relied upon the data verified from the books of accounts of the

company for determining net sales realization of the domestic industry. The Authority further notes that the period of investigation for the two cases are different and it is required to consider information with regard to the period of investigation of the present investigation. Once the POI has been fixed, the Designated Authority is required to consider the performance of the domestic industry for the injury period and upto the investigation period. The Authority has found both adverse volume and price effect of dumped imports on the domestic industry in the present case.

f. With regard to performance of the domestic industry in sunset review POI vis-à-vis current POI, the mere fact that the non-injurious price of the domestic industry was lower than net sales realization during Sunset Review POI does not imply that the authority should consider monthly comparison between non injurious price and the net sales realization in the present case as well. Nor it implies that the domestic industry has not suffered injury in the present case. In the Sunset Review case, it was found that the volume of imports was low and the imports occurred only in selected few months of the period of investigation and therefore it was necessary to compare the prices for the respective months. However, in the present case, both imports as well as domestic sales have occurred throughout the investigation period.

g. As regards the request for imposition of Anti-dumping duty on reference price basis, it is to be noted that both the cost of production and import prices of the subject goods have increased in post POI and therefore any recommendation of antidumping duty in the form of reference price will defeat the objective of Antidumping duty and also cause severe injury to the domestic industry.

K. Indian industry's interest & other issues:

91. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties in general is to eliminate injury caused to the domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the Subject Territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
92. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product(s) manufactured by using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the antidumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practice; would prevent the decline of the domestic industry; and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

Conclusion

93. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that the product under

consideration has been exported to India from the subject Territory below its associated normal value, thus, resulting in dumping of the product. The domestic industry has suffered material injury in respect of the subject goods. The material injury has been caused by the dumped imports from the Subject Territory.

Recommendations

94. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti dumping duty is required to offset dumping and consequent injury. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods from the Subject Territory in the form and manner described hereunder.

95. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive antidumping duty as per amount specified in Col 9 of the table below is recommended to be imposed from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the European Union.

Duty Table

Sl. No	Sub-heading	Description of goods	Specification	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	2921.41	Aniline	Any	European Union	European Union	Any	Any	110.72	Per/Mt	US\$
2.	2921.41	Aniline	Any	European Union	Any	Any	Any	110.72	Per/Mt	US\$
3.	2921.41	Aniline	Any	Any	European Union	Any	Any	110.72	Per/Mt	US\$

96. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

97. An appeal against the order of the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

VIJAYLAXMI JOSHI, The Designated Authority